राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 221 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, मंगलवार ,02 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

बजट में आत्मनिर्भर भारत पर फोकस

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने से मिडिल क्लास मायूस

कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ का आवंटन

राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत, सरकार 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी

निजीकरण पर फोकस,हिस्सेदारी बेच कर1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य

पर्यावरण मंत्रालय का बजट 42% बढ़ा बैंक डूबे तो ग्राहकों को देंगे 5 लाख

बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई

स्वास्थ्य बजट में137 प्रतिशत का इजाफा , अब 2.23 लाख करोड़

नई दिल्ली, (एजेंसी)।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया।वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। इसमें मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा।सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी है। सरकार की बाजीगीरी से जहां शेयर बाजार बमबम हुआ, वहीं आम आदमी के हाथ निराशा लगी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए।इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 प्रतिशत करना चाहते हैं।कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है।

सरकार का राजकोषीय घाटा 1991 से शुरू हुए उदारीकरण के बाद सबसे ज्यादा है। राजकोषीय घाटा यानी जब सरकार की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च हो जाए। 1991 में यह जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। 2020-21 में यह जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए।इसके लिए हम अगले दो महीने में बाजार से मदद लेंगे। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च और 6.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। सरकार 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 प्रतिशत करना चाहती है। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है।

सबसे पहले बात आम आदमी की जरूरत से जुड़े पेट्रोल-डीजल की।वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस का प्रस्ताव रखा।इसका नाम होगा एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस।यह 2 फरवरी से ही लागू हो जाएगा।हालांकि, वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इसका आम आदमी पर बोझ नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है।इसी तरह कस्टम ड्यूटी लगने वाली शराब पर 100 प्रतिशत, मसूर की दाल पर 20 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर 20 प्रतिशत सेस का प्रस्ताव है, लेकिन आम आदमी पर इसका भी असर नहीं होगा।

सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी। इसके साथ ही कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपायी गयी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल होगी।कोरोना की वजह से ही इस बार हेल्थ बजट में 137 प्रतिशत का इजाफा हुआ। हेल्थ बजट अब 2.23 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसके लिए पिछली बार 94 हजार करोड़ रुपए रखे गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए और बजट मिलेगा। बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए देशभर में निमोकोक्कल वैक्सीन लगाई जाएगी। इस निमोनिया से हर साल 50 हजार बच्चों की मौत होती है। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स शुरू होंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल शुरू होंगे।

केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये सोमवार को 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा।वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021 . 22 का बजट पेश करते हुए कहा,

डिजिटल लेन . देन को और बढावा देने के लिये मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूं जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सरकार के इस बजट से मोबाइल खरीदने की चाह रखने वालों को झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगा। वहीं, कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इतना ही नहीं, सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसका मतलब है कि अब सोना-चांदी सस्ता होगा और मोबाइल महंगा।

सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कार्यान्वित की जाएंगी। वित्त मंत्री सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागजरहित आम बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।

सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पहली बार कागज रहित बजट पेश करते कहा कि सभी वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा। यह सभी वित्तीय निवेशकों का अधिकार होगा। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम-1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया। आम बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि नए ढांचे के तहत ज्यादातर निदेशक और बोर्ड तथा प्रबंधन स्तर के अधिकारी निवासी भारतीय होंगे। कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। सरकार ने बजट में बताया कि कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर फैसले लिए जा चुके हैं।

बजट में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समावेशी विकास पर जोर : प्रधानमंत्री

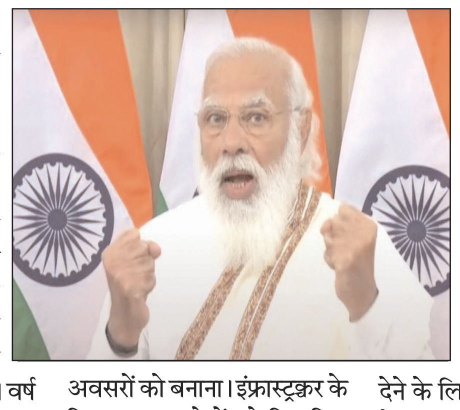

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर को अपनी प्रतिक्रिया दी।उन्होंने बजट को समावेशी विकास पर जोर देने वाला बताया।उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है।उन्होंने कहा कि आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं, वे हैं- ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना।युवाओं के लिए नए अवसरों को बनाना।इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए-नए क्षेत्रों को विकसित करना है। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं, जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही कितने सकारात्मक रिस्पॉन्स आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे थे कि सरकार आम लोगों पर बोझ बनाएगी, लेकिन सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इसमें सरकार ने देश में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत खर्च को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

क्या कहते हैं नेता

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल केवल बजट आवंटन में वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि योजनाओं का कार्यान्वयन भी होता है।

-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयकर भरने से छूट दी गई है। यह बुजुर्गों के लिए वरदान सिद्ध होगा। राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक उधारी की सीमा बढ़ाई गई है। राज्य भी जब इन्फ्रा में ज्यादा पैसा डालेंगे, तो आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नये वित्तीय विकास संस्थान का गठन किया गया है। इससे पूंजीगत योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था होगी।

-शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मप्र

केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के पुराने नारों की तरह अब आत्मनिर्भर के नए नारे के साथ आंकड़ों की हेराफेरी कर देश की जनता को गुमराह करने का काम इस बजट में किया गया है। जो लोग एफडीआई का विरोध करते थे वो आज एफडीआई को हर क्षेत्र में लागू कर रहे है। यह बजट पूरी तरह से आमजन विरोधी है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कोरोना की महामारी के भीषण संकट काल के समय आज आए देश के इस आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें थी लेकिन इस बजट से आमजन को भारी निराशा हुई है। कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

-कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मप्र

यह बजट 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के वादे पर अच्छा असर डालेगा। मूल रूप से प्लससः इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार का खर्च बढ़ा है। कमजोरियों के लिए सुरक्षा जाल का विस्तार और अधिक निजी निवेश के अवसर इस बजट में है।

-ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सदस्य

एयरपोर्ट, सड़कें, इंडियन ऑयल की पाइप लाइन, सरकारी बैंक, जनरल इंश्योरेंस और स्टेडियम भी सरकार बेचेगी। कुछ बचेगा तो 2024 तक सरकार बेच देंगी।

-अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

म्यांमार में सेना ने किया तख्तापलट, आंग सान सू की और सत्ताधारी पार्टी के कई नेता हिरासत में लिए गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को सोमवार की सुबह छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया है। म्यामांर में सेना ने तख्तापलट कर स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को नजरबंजद कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया कि सू ची और उनकी पार्टी के अध्यक्ष को सोमवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पोर्टल पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि नेपीता के लिए संचार के सभी माध्यम बंद कर दिये गये हैं और सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

पिछले साल के चुनाव के बाद म्यामांर के सांसद राजधानी नेपीता में संसद के पहले सत्र के लिए सोमवार को एकत्रित होने वाले थे। हालांकि, सेना के हालिया बयानों से सैन्य तख्तापलट की आशंका दिख रही थी। सू ची की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी जो बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं अधिक था। लेकिन वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में 25 प्रतिशत सीटें सेना को दी गयी हैं जो संवैधानिक बदलावों को रोकने के लिए काफी है। कई अहम मंत्री पदों को भी सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

सू ची (75) देश की सबसे अधिक प्रभावी नेता हैं और देश में सैन्य शासन के खिलाफ दशकों तक चले अहिंसक संघर्ष के बाद वह देश की नेता बनीं। म्यामांर में सेना को टेटमदॉ के नाम से जाना जाता है। सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया हालांकि वह इसके सबूत देने में नाकाम रही। देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमिशन ने पिछले सप्ताह सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था।

इन आरोपों से पिछले सप्ताह उस वक्त राजनीतिक तनाव पैदा हो गया जब सेना के एक प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सैन्य तख्तापलट की आशंका से इनकार नहीं किया। मेजर जनरल जॉ मिन तुन ने कहा था कि सेना संविधान के मुताबिक कानून का पालन करेगी।

कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने भी बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो संविधान को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती से सैन्य तख्तापलट की आशंका बढ़ गयी।

हालांकि शनिवार को सेना ने तख्तापलट की धमकी देने की बात से इनकार किया और अज्ञात संगठनों एवं मीडिया पर उसके बारे में भ्रामक बातें फैलाने तथा जनरल की बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सेना ने रविवार को भी अपनी बात दोहराते हुए तख्तापलट की आशंका को खारिज किया और इस बार उसने विदेशी दूतावासों पर सेना के बारे में भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया।

केंद्र सरकार के बजट पर कांग्रेस का हमला, कहा- जीडीपी की रिकॉर्ड गिरावट का जिक्र नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने बजट-2020-21 पेश किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का जिक्र नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया,वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है। 1991 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने दावा किया कि देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा बजट में कोई मुख्य ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाओ, सिर्फ देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इसमें सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद द्वारा पास तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 66वें दिन भी जारी है। किसानों के ?प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका है। हाल ही में सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार किसानों को दिए गए सभी प्रस्तावों पर आज भी कायम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था की बातचीत के जरिए ही इसका हल निकाला जा सकता है।

आपको बता दें कि किसानों ने पहले एक फरवरी यानी आज के दिन संसद मार्च की घोषणा की थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के दि[n] ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले हिंसा के बा[द] उन्होंने इसे रद्द कर दिया। हालांकि दिल्ली मे जहां-जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। ट्रैफिक में भी बदलाव कि[ए] गए हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा विपक्ष यहां पर वोट तलाशने नहीं आए। विपक्ष यहां हमदर्दी के लिए आता है। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।

वहीं, इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हु[ए] कहा कि वह देश के बड़े राजनेता हैं और कृषि से जुड़े विषयों पर बड़ी जवाबदेही के साथ बात करते रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं जब वे कृषि मंत्री थे उन्होंने कृषि सुधार करने की कोशिश की थी। आज उनके कुछ ट्वीट आए, उन्हें देखकर मुझे निराशा हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार जी के सामने बिल के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया होगा। मैं आशा करता हूं कि वे सही तथ्यों को समझेंगे और कृषि सुधार बिल पर अपनी राय को बदलेंगे।

यूथेनेशिया पर बहस:पुर्तगाल की संसद ने इच्छामृत्यु का बिल पास किया

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ऐसा करने वाला 7वां देश बन जाएगा

लिस्बन। पुर्तगाल की संसद ने यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है। इसके पक्ष में 136 और विरोध में 78 वोट डाले गए। अब यह बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके दस्तखत करने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही पुर्तगाल इच्छामृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा और दुनिया का 7वां देश बन जाएगा।

संसद के फैसले का विरोध भी शुरू

कैथोलिक धर्म को मानने वालों ने संसद के इस कदम का विरोध किया है । कैथोलिक पुर्तगाल का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा, 12 प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने भी राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु को रोकने के लिए दखल देने की अपील की है। स्टॉप यूथेनेशिया मूवमेंट ने कहा कि ऐसे समय में जब हजारों लोग और इंस्टीट्यूट हर रोज बीमार और कमजोर लोगों की देखभाल कर उनका जीवन बचाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, इच्छामृत्यु को मंजूरी देना उनका अपमान होगा।

बिल के मुताबिक, इच्छामृत्यु के लिए जरूरी शर्तें

इच्छामृत्यु चाहने वाले शख्स की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

उसे गंभीर चोट या कोई ऐसी घातक बीमारी हो जिसका इलाज मुमकिन न हो।

उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो और वह पूरे होश में हो।

ऐसी हालत में डॉक्टरों की सलाह पर ही उसे इच्छामृत्यु दी जा सकती है।

बिल में प्रावधान है कि डॉक्टर और नर्स इच्छामृत्यु देने से इनकार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की इजाजत मांगी जा सकती है।

राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल कर मामले को कोर्ट भेज सकते हैं या सीधे खारिज कर सकते हैं।

भारत में भी उठती रही है मांग

भारत में भी इच्छामृत्यु की मांग उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल तक कोमा में रहीं नर्स अरुणा शानबाग के मामले की सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर इच्छामृत्यु देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। इसके लिए पैसिव यूथेनेशिया शब्द का इस्तेमाल किया गया।

इसका मतलब है किसी बीमार शख्स का इलाज रोक देना, ताकि उसकी मौत हो जाए। अरुणा की एक सहेली ने 2011 में उनके लिए इच्छामृत्यु की मांग की थी। बाद में अरुणा की मौत हो गई थी।

इन देशों में इच्छामृत्यु वैध

नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कोलंबिया, लग्जमबर्ग, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एक्टिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता मिली हुई है। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई बड़े देश इसके खिलाफ हैं। कई साल की बहस के बाद 2016 में कनाडा ने इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी थी।

पड़ोसी का प्रोपेगैंडा:यूएस में पाकिस्तान ने कहा- किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भारत हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है

वाशिंगटन। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने दुनिया को चेतावनी देने वाले अंदाज में फिर दावा किया कि भारत इस्लामाबाद को लेकर अपने आक्रामक रवैये को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत में चल रहे

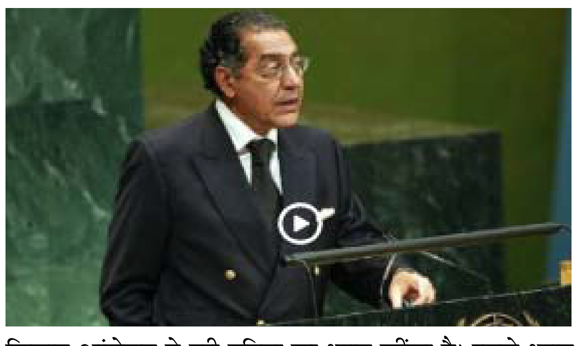

किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इससे ध्यान हटाने के लिए भारत सरकार ऐसे ऑपरेशन की कोशिश कर सकती है।

फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है, जहां किसी ऑपरेशन को पूरा करने वाले की पहचान छिपा ली जाती है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला अगर पकड़ा जाता है, तो उससे पूरी तरह मुंह फेर लिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन करने वालों को यह पता होता है कि अगर वे पकड़े गए तो सरकार उन्हें कभी अपना नहीं मानेगी।

सुरक्षा परिषद में भारत की सीट पर अड़ंगा लगाने की कोशिश

जी-4 देश भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के रास्ते में अड़ंगा डालने के लिए पाकिस्तान ने यह पैंतरा अपनाया है। पहले भी अहम मौकों पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस तरह का प्रोपेगैंडा फैलाता रहा है।

कश्मीर में आवाज दबाने का आरोप लगाया

यूएस में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के फैसले लेने के अधिकार को दबा दिया है। उसकी सेना वहां लोगों पर अत्याचार कर रही है। मुस्लिमों की ज्यादा आबादी वाले राज्य को हिंदू बहुल क्षेत्र में बदलने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह अपराध है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने ऑपरेशन के जरिए कश्मीरियों को चुप करा दिया है।

पुलवामा हमले का भी जिक्र

अकरम ने कहा कि फरवरी, 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से युद्ध जैसे हालात बना दिए थे। पाकिस्तान ने संयम दिखाकर उसे रोक दिया था। अकरम ने दावा किया कि पुलवामा हमले में स्थानीय लोग शामिल थे। पाकिस्तान से इसका कोई जुड़ाव नहीं है।

बाइडन प्रशासन में आधी आबादी का दबदबा, महिला हिस्सेदारी का बना रिकॉर्ड

वाशिंगटन। अमेरिकी प्रशासन में आधी आबादी का दबदबा है। जी हां, अमेरिका के निवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम में महिलाओं की हिस्सेदार पूर्व के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बाइडन प्रशासन में महिलाओं को खास तवोज्जह दी गई है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडन ने अपने प्रशासन में ने अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर 13 महिलाओं को जगह दी है। इसमें कई भारतीय मूल की महिलाएं भी शामिल हैं। बाइडन यह संकेत दे चुके हैं कि उनके प्रशासन में अभी और महिलाओं को जगह दी जाएगी। बाइडन ने कहा कि वह अपने प्रशासन को विविध बनाएंगे, जो देश की विविधता और उसकी संस्कृति को दर्शाएगा।

भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस लगातार सुर्खियों में रही हैं। अब अमेरिका में पहली बार एक महिला को वित्त मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। देश में पहली बार किसी महिला को वित्त मंत्री पद की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। अमेरिका की प्रख्यात अर्थशास्त्री जेनेट येलन ने मंगलवार को अमेरिका की पहली महिला वित्तमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। येलन को कार्यभार की शपथ उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिलाई। इसके पूर्व वह केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की गवर्नर रह चुकी हैं। बाइडेन ने कहा कि वो अपने प्रशासन को विविध बनाएंगे, जो देश की विविधता और उसकी संस्कृति को दर्शाएगा। बाइडन ने अपनी प्रेस टीम में सर्फि महिलाओं को ही स्थान दिया है। ऐसा करने वाले वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। प्रेस टीम की सात सदस्यीय टीम का नेतृत्व केट बेडिंगफील्ड करेंगी। केट इसके पहले बाइडन के चुनावी कैंपन की डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। सके अतिरिक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रवक्ता जेन साकी को प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं भारतवंशी नीरा टंडन को भी बाइडन प्रशासन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। नीरा को बाइडन की नीतियों पर अमल की देखरेख करने की जिम्मेदारी होगी।

वनीता गुप्ता को कानून मंत्रालय का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। बाइडन ने विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी उजरा जेया को असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लिए अवर विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है।माला अडिगा को प्रथम महिला डॉ जिल बाइडन की नीति निदेशक और गरिमा वर्मा को प्रथम महिला के कार्याकाल की डिजिटल निदेशक नियुक्त किया गया है। सबरीना सिंह को उनकी उप प्रेस मंत्री नियुक्त किया गया है। कश्मीर से संबंध रखने वाली आयशा शाह को व्हाइट हाउस कार्यालय की डिजिटल रणनीति की 'पार्टनरशिप मैनेजर' और समीरा फाजली को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् की उप निदेशक नामित किया गया है।

कोरोना दुनिया में: पाकिस्तान को मार्च में वैक्सीन के 60 लाख डोज मिलेंगे, चार देशों में अब भी रोज 1 हजार से ज्यादा मौतें

वाशिंगटन। कोरोना की दूसरी मार झेल रहे पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। देश की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चीन की सिनाफार्म, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका और रूस की स्पूतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल की मंजूरी दी है।

पाकिस्तान ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर असद उमर ने शनिवार को बताया कि 2021 के फर्स्ट हाफ से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 1.7 करोड़ डोज की सप्लाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह 'गुड न्यूज' दी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स प्लेटफार्म से उन्हें लेटर मिल गया है। देश को वैक्सीन के 60 लाख डोज मार्च में मिल जाएंगे। उन्होंने लिखा कि हमने वैक्सीन की उपलब्धता तय करने के लिए आठ महीने पहले कोवैक्स के साथ करार कर लिया था।

इस बीच, प्रधानमंत्री स्पेशल असिस्टेंट हेल्थ डॉ. फैसल सुल्तान ने बताया कि शुरुआत में सिनोफार्म वैक्सीन के पांच लाख और एस्ट्राजेनेका के 70 लाख डोज मिलेंगे। इन्हें लोगों को फ्री में लगाया जाएगा। पाकिस्तान में अगले हफ्ते वैक्सीन ड्राइव शुरू सकती है। पहले फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। कोवैक्स WHO का बनाया अलायंस है। यह दुनिया की 20त्न आबादी को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। पिछले अप्रैल में बनाए गए इस अलायंस में पाकिस्तान भी शामिल है।

अब तक 10.31 करोड़ के ज्यादा मरीज

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.31 करोड़ के ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 29 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

अमेरिका में हर दिन ब्रिटेन से दोगुनी मौतें

अब सिर्फ 4 देश हैं, जहां हर दिन 1 हजार से

ज्यादा मौतें हो रही हैं। इनमें अमेरिका सबसे आगे है। यहां शनिवार को 2889 मरीजों ने दम तोड़ा। इसके बाद मैक्सिको में 1434, ब्रिटेन में 1200 और ब्राजील में 1196 मौतें हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के मरीजों के मामले में 13वें नंबर पर मौजूद मैक्सिको हर दिन हो रही मौतों में दूसरे नंबर पर है। यहां 18,41,893 मरीज हैं।

पुतिन का 'सीक्रेट महल': 1000 करोड़ रुपये कीमत, 16 देशों की GDP इससे कम; दावा- महल में सारी लग्जरी सुविधाएं

वाशिंगटन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 'सीक्रेट महल' जेलेंजिक शहर में ब्लैक सी यानी काला सागर के पास स्थित है। 170 एकड़ में फैला महल परिसर 40 बाग-बगीचों से घिरा है। इसकी कीमत डेढ़ बिलियन डॉलर (करीब 1000 करोड़ रु.) से भी ज्यादा है। सीरिया, माइक्रोनेशिया, ग्रेनेडा, समोआ, और किरिबाती जैसे 16 देशों की GDP भी इससे कम है। दरअसल, पुतिन विरोधी और विपक्ष के नेता एलेक्सी नवेलनी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

इसमें उन्होंने दावा किया था कि- 'पुतिन के महल की कीमत एक हजार करोड़ रु. है। महल का मुख्य हिस्सा 1.90 वर्गफीट में फैला है। इसमें 11 बेडरूम, दो हैलीपेड, कैसीनो, प्राइवेट बार, थियेटर, पोल डांस बार समेत कई लग्जरी सुविधाएं हैं। यहां 260 फीट लंबा फुट ब्रिज भी है।' यह वीडियो सामने आते ही रूस के 100 से ज्यादा शहरों में पुतिन विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग नवेलनी के समर्थन में उतर आए। इसके बाद पुलिस ने नवेलनी के पत्नी समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वहीं, शुक्रवार को नवेलनी के टीम ने महल के अंदर की तस्वीरें भी पोस्ट कीं। जिसके बाद हजारों युवा सड़कों पर उतर आए।

वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया

नवेलनी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को लोग खोज-खोजकर देख रहे हैं। 17 जनवरी को नवेलनी की गिरफ्तारी के बाद से अब तक इस वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। लोग माइनस 51 डिग्री में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

रिपोर्ट: मॉस्को में 5 बड़ी जेलें, सभी भर गईं: रूस में 923 जेलें हैं। इनमें से 5 बड़ी जेलें राजधानी मॉस्को में हैं। लेकिन पुतिन विरोधी प्रदर्शनों के बाद मॉस्को की सभी जेलें प्रदर्शनकारियों से भर गई हैं। इसके चलते गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों

को बस और ट्रकों में रखा जा रहा है। मॉस्को की जेलें सबसे खतरनाक मानी जाती हैं।

सर्वे: 42 फीसदी युवा पहली बार सड़कों पर उतरे: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ 42 फीसदी लोग पहली बार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सर्वे में यह बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक, रूस के सभी शहरों के लोग पुतिन विरोधी नवेलनी को अपना समर्थन दे रहे हैं। लोगों की मांग है कि नवेलनी को जल्द रिहा किया जाए।

डब्ल्यूएसओ की टीम ने हुनान सीफूड मार्केट का किया दौरा, कोरोना की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश

वुहान। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जांच करने चीन पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दल ने रविवार को वुहान के हुनान सीफूड मार्केट का दौरा किया। टीम के सदस्यों को वुहान के सबसे बड़े वेट मार्केट में से एक बइशाजू मार्केट से गुजरते हुए देखा गया। उनके साथ चीनी अधिकारियों और प्रतिनिधियों का दल भी था। दल अब तक दो अस्पतालों का दौरा कर चुका है। इससे पहले शनिवार को वे वुहान के एक अस्पताल में पहुंचे। 14 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम गत 14 जनवरी को वुहान पहुंची थी और 14 दिनों तक क्वारंटाइन रही। जिनयांतन अस्पताल शहर के उन चुनिंदा अस्पतालों में से एक है जहां 2020 की शुरुआत में अज्ञात वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज किया गया था। बता दें कि दल ने शुक्रवार को चीन के वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की थी और वुहान के उस अस्पताल का दौरा किया, जहां चीन के मुताबिक एक वर्ष पहले कोरोना के पहले मरीज का उपचार किया गया था। डब्ल्यूएचओ के दल में पशु स्वास्थ्य, विषाणु विज्ञान, खाद्य सुरक्षा एवं महामारी विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने कोरोना के प्रारंभिक इतिहास को समर्पित एक म्यूजियम का भी दौरा किया। चीन के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मरीज का इलाज हुबेई इंटिग्रेटेड चाइनीज एंड वेस्टर्न मेडिसीन हॉस्पिटल में हुआ था।

यूएस की कंपनी का सीरम से करार

नोवावैक्स दिवालिया होने वाली थी, भारतीय मूल की वैज्ञानिक के नेतृत्व में महिलाओं ने वैक्सीन बनाकर दी संजीवनी

न्यूयॉर्क। कोरोना के नए स्ट्रेन में अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन 86फीसदी प्रभावी पाई गई है। ब्रिटेन, अमेरिका और मैक्सिको में इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने भी देश में इस वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है। कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के प्रेसिडेंट ग्रेगोरी मार्क ग्लेन कहते हैं, 'जल्द ही वैक्सीन बाजार में होगी।'

दिलचस्प बात यह है कि दो साल पहले नोवावैक्स दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज की सूची से भी बाहर हो गई थी। मैरीलैंड की दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के हाथों बिकने जा रही थी। लेकिन इस बीच महामारी आ गई। अब कंपनी ने अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज का करार किया है।

जल्द ही वैक्सीन बाजार में होगी

इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नोवावैक्स की इस वैक्सीन को कोवोवैक्स के नाम से जून 2021 तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है, इस वैक्सीन को महिला वैज्ञानिकों की टीम बना रही है, जिसका नेतृत्व भारतीय मूल की वैज्ञानिक नीता पटेल कर रही हैं।

टीम 18 घंटे काम कर रही

महिला वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर नीता पटेल कहती हैं, 'मैं समझती हूं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का लैब में होना अधिक सामान्य बात है। हमने कोविड वैक्सीन पर बीते साल 10 जनवरी को

काम शुरू किया था और तब से लैब एक दिन भी बंद नहीं हुई है। टीम 18 घंटे काम कर रही है। इस टीम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।' नीता एक बेबाक और विनम्र महिला हैं। वे काम की गंभीरता को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी टीम का काम कितना ऐतिहासिक है।

यूएस चीन टकराव: अमेरिका ने कहा- दक्षिण चीन सागर में मित्र देशों की हिफाजत हमारा फर्ज; चीन से निपटने की तैयारी

न्यूयॉर्क। 10 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तब भी हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका और चीन की नेवी साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में फिर आमने-सामने हो गई हैं। 6 महीने में यह दूसरा मौका है जब चीन और अमेरिका के वॉरशिप इस इलाके में आमने-सामने हैं।

चीन की इस हरकत पर अमेरिका सतर्क है। गुरुवार को उसने कहा- इस इलाके में मौजूद मित्र देशों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। कहा- ताइवान के साथ चीन जो कर रहा है, उस पर हमारी नजर है। हालांकि, फौरन किसी टकराव का खतरा नहीं दिखता।

यूएसएस रूजवेल्ट के जरिए मैसेज: बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद चीन ने शायद अमेरिका का रिएक्शन जानने के लिए साउथ चाइना सी और ताइवान के ऊपर फाइटर जेट्स उड़ाए। उसका वॉरशिप यहां पहले से ही तैनात है। अमेरिका ने बिना देरी किए अपने सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स में से एक यूएसएस रूजवेल्ट को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया। इसके बाद से इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस वॉरशिप पर अमेरिकी नेवी के 14 फाइटर जेट्स और 21 हेलिकॉप्टर मौजूद हैं। इतना ही नहीं यह न्यूक्लियर वॉर फेयर का भी एक अहम हथियार है। चीन के पास इसका जवाब नहीं है।

टकराव का इरादा नहीं

साउथ चाइना सी में बने हालात पर अमेरिकी रक्षा विभाग ज्यादा बोलने के तैयार नहीं है। पेंटागन ने एक बयान में कहा- टकराव की आशंका को हम खारिज करते हैं। हमारा थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां मौजूद है। चीनी सेना की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हमें नहीं लगता कि वो अमेरिकी सेना के लिए कोई मुश्किल खड़ी करेंगे।

हर देश से चीन की दुश्मनी

चीन ताकत के जरिए साउथ चाइना सी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यहां मौजूद हर देश के साथ उसका झगड़ा और तनाव है। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपीन्स, ताइवान और वियतनाम पर वो अपनी नेवी और एयरफोर्स के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प के दौर में ही अमेरिका ने साफ कर दिया था कि इस इलाके के किसी भी देश पर हमला किसी भी सूरत में अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ट्रम्प ने नवंबर के पहले हफ्ते में कहा था- इस इलाके के किसी भी देश पर हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा और उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा।

क्यूबा में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 25 घायल

हवाना। कैरेबियन में स्थित क्यूबा में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास ही एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा आयोग ने बताया कि राजधानी हवाना के लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में सड़क दुर्घटना के बाद क्यूबा में यह घटना हुई। स्थानीय प्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक, बस के ड्राइवर ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस एक पुल पर गिर गई।

20 मिनट में तैयार हो जाएगी 500 किलो दाल, एक बार में बनेंगी 4000 रोटियां

नई दिल्ली। समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में लंगर के लिए आधुनिक मशीनों को लगाकर संगतों को रसोई सौंप दिया है। रसोई का सुंदरीकरण भी किया गया है। इसके साथ ही नया लंगर हॉल भी खोल दिया गया है।

रविवार को कार सेवा वाले बाबा बचन सिंह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नई मशीनों से एक समय में 500 किलो दाल मात्र 20 मिनट में तैयार हो सकेगी, वहीं डेढ़ क्विंटल आटा एक बार में मशीन से गूंथा जा सकता है। इसी के साथ ही दो मशीनों के माध्यम से एक बार में चार हजार रोटियां बन सकेंगी। इसके लिए यहां पर बड़े-बड़े बायलर कुकर लगाए गए हैं।

इससे लंगरियों के समय की बचत होगी। अब उन्हें रात से ही इसकी तैयारियां नहीं करनी होगी। उधर, कमेटी के महासचिव हरमीत सिंह कालका ने बताया कि कोरोना काल में लगे लाकडाउन में कमेटी ने लाखों लोगों को लंगर बनाकर भेजा था, लेकिन इसे बनाने के लिए कई स्थानों का उपयोग किया गया था। नई मशीनें लगने के बाद अब एक ही स्थान पर लाखों लोगों के लिए लंगर तैयार किया जा सकता है। लंगर खाने की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग, छोटे-बड़े सब एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी सिख बसे हुए हैं, उन्होंने इस लंगर प्रथा को कायम रखा है। वहीं, लंगर के कई अर्थ होते हैं। मसलन जहाज, नाव आदि में सफर करने वाले लोग अक्सर लंगर डालकर भोजन आदि कर विश्राम करते थे। वर्तमान में लंगर का अर्थ एक जगह सामूहिक रूप से खाने को ही कहा जाता है।

नजफगढ़ के झटीकरा और रावता इलाके में तेंदुए का खौफ, सड़क किनारे बैठे तस्वीर हो रही शेयर

नई दिल्ली। पिछले पांच दिनों से एक तेंदुआ नजफगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा है, लेकिन अभी तक यह पकड़ से बाहर है। शुरुआत में नजफगढ़ के सबसे प्राचीन रघुनाथ मंदिर के आसपास सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद नजफगढ़ क्षेत्र के लोग सांसत में थे। इस दौरान थाना भी सतर्क हो गया था।

वायरल वीडियो के आधार पर सीमा की प्रमुख चौकियों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का भी इत्तला कर दिया था। इस दौरान नजफगढ़ बाजार क्षेत्र में आने जानेवालों को चौकस कर दिया गया था। रात के समय पैदल, स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने से मनाही थी। अभी नजफगढ़ बाजार के लोग दहशत से उबरे नहीं थे कि दूसरे दिन यही तेंदुआ पंडवाला कलां गांव के आसपास की झाड़ियों में दिख गया। इससे ग्रामीण बैचेन हो उठे। तीसरे और चौथे दिन झटीकरा गांव के समीप सड़क के किनारे दो दिन बैठा रहा। इसके बाद से शहर से लेकर गांव तक के लोग दहशत में जी रहे हैं। हालांकि, अब सूचना के आधार पर वन विभाग ने आस पास की झाड़ियों में जाल भी लगाया। लेकिन तेंदुआ यहां से निकल चुका था। अब वन विभाग को तेंदुए का रावता झील, रावता बांध और खेतों के आस पास होने का अनुमान है इसलिए यहां पर पिंजरा लगा दिया है। ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है।

बातचीत में झटीकरा पुलिस पीकेट पर तैनात होमगार्ड के जवान ललित कुमार ने बताया कि 27 जनवरी को तेंदुए की नजफगढ़ के बाजार में होने की सूचना मिली। यह तेंदुआ 28 व 29 जनवरी को झटीकरा बांध के समीप सड़क किनारे बैठा मिला। यहा से गुजर रहे कार सवारों ने बारी बारी से बताते गए। इन चार चश्मदीदों ने तेंदुए के सड़क किनारे बैठे होने की फोटो भी शेयर की।

30 जनवरी को वन विभाग ने जाल लगाकर खोज बिन की थी, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। वन विभाग के अधिकारी देवेंद्र यादव और वन्य जीव सरंक्षण विभाग के निरीक्षक आरआर मीना की देखरेख उनकी टीम रावता में तेंदुए की तलाश में जुटी है। देवेंद्र यादव ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि 30 जनवरी को यह तेंदुआ रावता बांध से रावता के खेतों में जाते हुए देखा गया है। इसके आधार पर रावता बांध पर एक पिंजरा लगा दिया गया है। तेंदुए की कहीं और होने की सूचना मिले तो उस क्षेत्र में एक पिंजरा लगाया जा सके। इसलिए एक और पिंजरे का भी इंतजाम कर लिया गया है।

इनका कहना है कि अभी तक तेंदुए ने किसी को चोट नहीं पहुंचाया है किसी तरह की जानमाल की क्षति सूचना नहीं मिली है। ऐसे में तेंदुए के आदमखोर होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर रावता में तेंदुआ मौजूद होगा तो जरूर पकड़ में आ जाएगा। इस दौरान तेंदुआ घायल हो सकता है इसलिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भी बुला लिया गया है। इन्होंने यह भी संभावना जताई कि हो अमूमन, अरावली की पहाड़ियों में इस तरह के तेंदुए के घुमने की सूचना आती रहती है। ऐसी संभावना है कि वह रात में रास्ता भटक गया हो और अब रावता बांध के सहारे अरावली की पहाड़ियों की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हो।

दिल्ली में घुस नहीं पाएंगे किसान, टीकरी बॉर्डर पर सड़क खोदकर लगाई नुकीली कीलें

नई दिल्ली। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। पहले यहां पर सीसी की दीवार बनाई गई थी। सात लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी, मगर अब सड़क खोदकर उसमें लंबी-लंबी कीलें व नुकीले सरिया लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर और भी मजबूत कर दिया गया है। बॉर्डर पर रोड रोलर भी अब खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान अगर दिल्ली में घुसने का प्रयास करें तो उन्हें रोकने के लिए रोड रोलर को सड़क पर खड़ा किया जा सके। यहां पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बॉर्डर पर ही थी। इसके बाद टीकरी कलां गांव तक जगह-जगह बैरिकेडिंग की दीवार खड़ी कर दी थी। टीकरी बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस की ओर से सीसी की दीवार बना दी गई थी। चार फीट मोटी यह दीवार बनाई गई है। इसके 10 कदम पर दिल्ली की तरफ एमसीडी टोल के पास बॉर्डर पर ही सड़क खोद कर उसकी जगह पर सीमेंट में लोहे की कीलें लगवा दी गई हैं। साथ ही लोहे के सरिया नुकीले बनवाकर यहां पर लगवा दिए गए हैं, ताकि कोई भी वाहन यहां से गुजर ना सके। यहां से लोगों के आने-जाने में भी काफी परेशानी होगी। कीलों से गुजरने में वाहन का पंक्चर हो जाएगा। पूरा टायर ही खराब हो जाएगा। यहां से निकलना अब मुश्किल होगा। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की 15 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद यहां हर रोज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसी कड़ी में लोहे की कीलें लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यहां से किसी भी किसान को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी किसान यहां से निकलकर दिल्ली की सीमा में घुस सके। उधर, हर रोज बढ़ी रही सुरक्षा व्यवस्था व बैरिकेडिंग से किसानों में भी डर फैल रहा है। किसानों का कहना है कि देश के अन्नदाता को रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि हम किसान नहीं बल्कि कोई उपद्रवी हों। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने के लिए सिंघु बार्डर पर पुलिस की ओर से अब सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी की जा रही है। इसी के मद्देनजर बैरिकेड्स को अब वेल्ड कर उनके बीच की जगह में रोड़ी, सीमेंट आदि डाल कर मजबूती दी जा रही है।

गुजरात की फारेंसिक टीमें करेंगी दिल्ली में हुए उपद्रव की जांच

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की आड़ में हिंसा करने वाले उपद्रवी किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। उपद्रव के तमाम डिजिटल सबूतों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात के नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) की दो टीमों को दिल्ली बुलाया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब दिल्ली में सीबीआइ की सीएफएसएल व दिल्ली सरकार की फारेंसिक साइंस लैब होने के बावजूद गुजरात की एनएफएसयू से छह-छह सदस्यीय दो टीमों को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने व दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भीषण उपद्रव करने की घटना ने भारत की छवि को खराब करने का काम किया। इसलिए सरकार ने उक्त मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रलय चाहता है कि साक्ष्यों के स्तर में किसी भी तरह की चूक न होने पाए। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनएफएसयू की दोनों टीमें

शनिवार रात दिल्ली पहुंच गई हैं। टीमें लाल किला व आइटीओ समेत सभी घटनास्थलों का मुआयना करने के साथ सभी डिजिटल सुबूतों की बारीकी से जांच करने में जुट गई हैं। यही नहीं जांच पूरी होने तक दोनों टीमें दिल्ली में ही रहेंगी। गुजरात की फारेंसिक टीमें न केवल क्राइम ब्रांच की एसआइटी में ट्रांसफर किए गए नौ प्रमुख मामले, बल्कि लाल किला, आइटीओ, नजफगढ़, नांगलोई, बाबा हरिदास नगर, गाजीपुर, पांडवनगर व समयपुर बादली में किए गए उपद्रव मामले के वीडियो, आडियो व सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेंगी। इसके अलावा स्थानीय थाना पुलिस द्वारा की जा रही जांच में भी सहयोग करेंगी। उपद्रव की विस्तृत साजिश रचे जाने की जांच कर रही स्पेशल सेल को भी फारेंसिक एक्सपर्ट की टीम सहयोग करेगी। उपद्रव मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज, कैमरे व मोबाइल से बनाए गए वीडियो व तस्वीरें ही सबसे अहम सबूत हैं। उपद्रव स्थल के चारों तरफ की सड़कों का मुआयना कर पुलिस ने कैमरों की जानकारी जुटाई है। इसमें कई मार्गों पर सरकारी अथवा निजी कार्यालयों, घरों व दुकानों के बाहर भी कैमरे लगे हैं, इसलिए पुलिस ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों व आम लोगों को पत्र भेजकर कैमरे की फुटेज मुहैया कराने का अनुरोध किया है। सीबीआइ की सीएफएसएल व दिल्ली सरकार की फारेंसिक साइंस लैब होने के बावजूद गुजरात की टीमों को बुलाया गया है। दरअसल, एनएफएसयू के बारे में दावा है कि यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां फारेंसिक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मामलों से जुड़ी चीजों का सबसे बेहतर शोध होता है। सूत्रों की मानें तो गुजरात की एनएफएसयू के पास डिजिटल सुबूतों की जांच के लिए इस वक्त सबसे उन्नत तकनीक है।

सीएम केजरीवाल ने कहा बजटे से बढ़ेगी महंगाई
सिसोदिया बोले- दिल्ली को किया निराश

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस बजट को जहां केंद्र सरकार और भाजपा नेता जनता के लिए बेहतर बता रहे हैं वहीं विपक्ष इसकी निंदा कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चंद बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। उन्होंने दावा किया कि इस बजट से महंगाई के साथ आम जन-मानस की समस्याएं बढ़ेगी। वहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली को फिर से निराश किया है। दिल्ली को बजट में केवल 325 करोड़ मिले है जबकि राजधानी के लोग 1.5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भाजपा शासित नगर निगम को एक भी रुपया नहीं दिया, जबकि देश भर के नगर निगमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। निगम चुनाव के वक्त भाजपा ने कहा था कि वे केंद्र से सीधे एमसीडी के लिए पैसा लाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए बजट में शिक्षा का बजट पिछले साल से 6000 करोड़ कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि हृश्वक्कमें शिक्षा बजट लृष्क्क का कम से कम 6 फीसद करने की नीति बताई गई है। उन्होंने कहा कि बजट में साफ बता दिया गया है कि नई शिक्षा नीति भाजपा के लिए केवल एक जुमला भर थी। इतिहास गवाह है कि परिवार हों या देश, आत्मनिर्भर वही बनता है जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पर खर्च करता है। यहां तो शिक्षा का बजट 6000 करोड़ कम किया जा रहा है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश आत्मनिर्भर कैसे होगा आत्मनिर्भर बनाने की बात भी केवल जुमला ही है।

दिल्ली से सटे पलवल में भारी सुरक्षा बल तैनात
दोबारा धरने पर नहीं दिया जाएगा किसानों को बैठने

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सिंघु बॉर्डर पर चल रहा है किसानों का धरना-प्रदर्शन सोमवार को 67वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र गाजीपुर बॉर्डर पर बना हुआ है। हालात के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने अक्षरधाम के पास नोएडा के लिए वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। वहीं, दिल्ली से सटे पलवल जिले में तनाव को देखते हुए मौके पर आरएएफ और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एसपी दीपक गहलावत का कहना कि दोबारा यहां पर धरना देने की नहीं अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसू देखने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर बृहस्पतिवार

रात से ही किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच रविवार को राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है। हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा का कि सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है। किसान तभी घर लौटेंगे जब नये कानून वापस ले लिए जाएंगे। नए कृषि कानूनों के विरोधी प्रदर्शनकारियों व स्थानीय ग्रामीणों के बीच शुक्रवार को हुए हिंसक टकराव के बाद सिंघु बार्डर पर लगातार सुरक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। रविवार को भी सुरक्षा के एक स्तर को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब यहां छह स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हो गई। शनिवार को पुलिस ने कुंडली से बिल्कुल सटे दिल्ली की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग की खोदाई कर दी थी। अब रविवार को गड्ढे के आगे भी सीमेंट बैरिकेड लगाने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस पहले से की गई पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए अब बार्डर पर टोल के निकट आठ फीट लंबे लोहे के पाइप से घेराबंदी की जा रही है। इन पर कनात लगाएं जाएंगे। रविवार को इसके लिए मजदूरों को जमीन पर निशान लगाने के साथ लोहे के पाइप वाहनों से उतारते देखा गया। पुलिस ने धरना स्थल के चारों तरफ पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी है। ऐसे में आम लोग धरना स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हिंसक टकराव की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों को छोड़कर किसी आम व्यक्ति को धरना स्थल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने सिंघु बार्डर से कुंडली की ओर जाने वाले लिंक रोड पर भी गड्ढे खोदकर दोनो तरफ सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस सिंघु बार्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा लिंक रोड पर अब तक कई गड्ढे खोद चुकी है।

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है बजट : अश्विनी राणा

नई दिल्ली। वॉयस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक अश्विनी राणा ने केंद्रीय बजट 2021-22 की तारीफ की है। बैंक एम एस एम ई और स्टार्टअप के लिये ऋण की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अश्विनी राणा ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में बैंक खाता धारकों को उनके डिपॉजिट की गारंटी को 1 लाख से 5 लाख किया था उसके प्रोविजन को तय किया जायेगा ताकि किसी भी बैंक के डिफाल्ट के कारण बैंकों के ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के उनके डिपॉजिट की गारंटी राशि का भुगतान हो सके। बजट में सरकार ने डूबे कर्जों के लिये एसेट्स रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाने का प्रस्ताव किया है जिसके माध्यम से बैंकों के उन खातों को जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है को इन एसेट्स रिस्ट्रक्चरिंग कम्पनियों को बेचकर बैंकों की बैलेंस शीट को साफ किया जाएगा और कम्पनी द्वारा ऋण की रिकवरी की जाएगी।

लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहे भारतीय टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग में तमाम आशंकाओं के बीच दोनों भारतीय टीके संजीवनी साबित हुए हैं। टीकाकरण अभियान शुरू होने के महज नौ दिन में ही न सिर्फ टीके ने लोगों का भरोसा जीता है, बल्कि दहशत के वायरस को भी ढेर कर दिया है। यही वजह है कि अब टीकाकरण अभियान के आगे बढ़ने के साथ ही दुष्प्रभाव के मामलों में भी कमी आ गई और अब दुष्प्रभाव के मामले न के बराबर बचे हैं। शुरुआत में टीकाकरण से दुष्प्रभाव के मामले जहां 1.18 फीसद आए थे, वहीं दो सप्ताह बाद यह महज 0.11 फीसद बचे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह स्वास्थ्य कर्मियों का टीके के प्रति विश्वास बढ़ना और डर खत्म होना है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि दोनों टीके (कोविशील्ड व कोवैक्सीन) पूरी तरह सुरक्षित हैं। खास तौर पर

सबसे ज्यादा चिंता स्वदेशी टीका कोवैक्सीन को लेकर थी, जो अब दूर हो गई है। दिल्ली में कोरोना के टीकाकरण के लिए सप्ताह में चार दिन निर्धारित हैं, इसलिए टीकाकरण शुरू होने के बाद अब तक दो सप्ताह में यहां नौ दिन टीकाकरण हुआ है। इस दौरान कुल 56,733 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया है। इसमें से सिर्फ 0.33 फीसद (192) स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की जगह पर दर्द, घबराहट इत्यादि जैसे हल्के दुष्प्रभाव देखे गए। इनमें से सिर्फ छह कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, जो अब ठीक हो चुके हैं। इनमें से तीन कर्मचारियों को कोविशील्ड व तीन कर्मचारियों को कोवैक्सीन टीका लगा था। दिल्ली में पहले दिन 4319 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा था, इसमें 51 लोगों में कुछ दुष्प्रभाव देखा गया था। 30 जनवरी को 8774 कर्मचारियों को टीका लगने के बाद सिर्फ 10 लोगों को कुछ परेशानी हुई। सफदरजंग अस्पताल के प्रिवेंटिव व कम्युनिटी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ. जुगल किशोर ने कहा कि शुरुआत में लोग टीके से घबराए हुए थे। यदि कोई पहले से तनाव में है तो टीका लगने के बाद घबराहट, सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। अब टीके को लेकर डर नहीं है। इसलिए टीकाकरण बढ़ने पर दुष्प्रभाव भी कम देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को टीके से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में अब तक टीका लगवाने वाले 94.91 फीसद स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड व 5.08 फीसद कर्मचारियों को कोवैक्सीन लगा है। इसका कारण यह है कि कोवैक्सीन सिर्फ केंद्र के छह अस्पतालों में ही उपलब्ध कराई गई है।

दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर दिखी वाहनों की लंबी कतारें

नई दिल्ली। पिछले तीन दिन से दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट बार्डर को बंद किया हुआ है। जिस वजह से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले वाहन चालक महाराजपुर बार्डर से जा रहे थे।

सोमवार को अचानक से पुलिस ने इस बार्डर को भी बंद कर दिया। दो बार्डर बंद होने से आनंद विहार, डेयरी फार्म, एनएच-9 पर भीषण जाम लग गया। पुलिस यातायात को अप्सरा बार्डर पर डायवर्ट कर दिया। इससे शाहदरा जीटी रोड, विकास मार्ग, वजीराबाद सहित कई सड़कों पर भीषण जाम लग गया। सुबह से जाम लगना शुरू हुआ और दोपहर तक भी वाहन चालक जाम से जूझ ही रहे हैं।

बार्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों के विरोध में एक फरवरी को बजट सत्र के दिन संसद तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव की वजह से प्रदर्शनकारियों ने मार्च स्थगित कर दिया था। आनंद विहार में वाहन चालकों को एक घंटे से ज्यादा समय जाम जाम से जूझना पड़ा, जाम के कारण लोग समय पर कार्यालय नहीं पहुंच सकें।

एनएच-9 पर भी वाहन रेंगते रहे। बार्डर के अलावा सड़कों पर जगह-जगह पुलिस बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच कर रही है, जिससे यमुनापार की दूसरी सड़कों पर भी जाम लग गया। जाम की वजह से आटो व कैब चालकों ने गाजियाबाद जाने से इन्कार कर दिया।

पुलिस ने जो सड़कें बंद की हुई है, उन सड़कों पर भी पुलिस ने राहगीरों को जाने नहीं दिया। दरअसल, पुलिस को आशंका थी कि किसानों ने भले ही मार्च स्थगित कर दिया हो, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी तरह से फिर से दिल्ली में घुसकर उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए कई जगहों पर रूट डायवर्ट कर दिया गया जबकि कई जगहों पर वाहनों की जांच की जाने लगी। ऐसे में लंबा जाम लग गया।

खुलेंगे लाल किले पर हिंसा के राज, 9 किसान नेताओं से क्राइम ब्रांच करेगा पूछताछ

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर लाल किला में उपद्रवियों का नेतृत्व करने वाले पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तीन दिनों से पुलिस की चार टीमें पंजाब के अलग-अलग इलाकों में दीप की तलाश में हैं, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ रहा है।

पुलिस का कहना है कि दीप अपना मोबाइल फोन बंद कर भूमिगत हो गया है। लेकिन, दीप सिद्धू घटना के बाद से कई बार फेसबुक लाइव होकर बयान जारी कर चुका है। शनिवार शाम को भी उसने फेसबुक पर कहा कि वह कुछ सुबूत जुटाने में लगा हुआ है। इसके बाद खुद दिल्ली पुलिस के समक्ष समर्पण कर देगा। बताया जा रहा है कि लाल किले पर उपद्रव के बाद मंगलवार शाम को ही दीप मौके से भाग गया था। तभी से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है, लेकिन फेसबुक पर लगातार सक्रिय है। विरोध जताने पर उसने कुछ किसान नेताओं को धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि अगर वह उनकी परतें खोलने पर आ गया, तब किसान नेताओं को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। उसने सफाई में कहा था कि उसने राष्ट्रीय ध्वज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने ध्वज फहरा कर सरकार को ताकत दिखाई है। उधर, तोड़फोड़ व उपद्रव करने वालों की पहचान करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियां लगातार लाल किले का दौरा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कई वाहन मालिकों व उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। गुजरात से आई फारेंसिक टीम ने भी रविवार को लाल किला, आइटीओ समेत कई जगहों का मुआयना किया। क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शनिवार को राकेश टिकैत समेत जिन नौ किसान नेताओं को पूछताछ में शामिल होने के लिए दोबारा नोटिस भेजा गया उन्हें सोमवार को क्राइम ब्रांच के अलग-अलग कार्यालयों में हाजिर होने को कहा गया है।

अब लौट भी आओ घर टीकरी बॉर्डर पर बैटे किसान प्रदर्शनकारियों को पंजाब से आ रहे संदेश

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद टीकरी बार्डर पर जमा आंदोलनकारियों के स्वजन काफी डरे हुए हैं और बार-बार फोन कर उन्हें घर वापस बुला रहे हैं। स्वजन कह रहे हैं कि अब आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है और कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे में घर लौटना ही बेहतर है। खासकर आंदोलनकारी महिलाओं को घर से सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं। हालांकि, ये अपने स्वजन को किसी तरह समझाकर आंदोलन की डगर पर डटे रहने की बात कह रहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में भी डर समाया हुआ है। पंजाब से आई जसप्रीत ने बताया कि लाल किले में हुई घटना के बाद मेरे घरवाले डर गए हैं। बार-बार फोन कर रहे हैं कि घर वापस आ जाओ। आंदोलन स्थल पर माहौल बिगड़ गया है। घरवालों को

खासकर आंदोलनकारी महिलाओं को घर से सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं। हालांकि ये अपने स्वजन को किसी तरह समझाकर आंदोलन की डगर पर डटे रहने की बात कह रहीं हैं लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में भी डर समाया हुआ है।

तो किसी तरह समझाया है, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा है। अगर इसी तरह के हालत उत्पन्न होते रहे तो घर जाना ही ठीक रहेगा। जसप्रीत ने कहा कि आंदोलन स्थल पर काफी परेशानी हो रही हैं। खासकर महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। 26 जनवरी को हुई घटना के बाद घरवालों का डरना लाजिमी है। एक अन्य आंदोलनकारी महिला नवनी ने बताया कि उनका भाई सिंघु बार्डर पर है और वह टीकरी बॉर्डर पर हैं। ट्रैक्टर परेड के नाम पर जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है। उनके घरवाले परेशान हो रहे हैं। दिन में कई बार फोन कर वे उनका हालचाल ले रहे हैं। यहां बैठे प्रदर्शनकारियों की मानें तो 26 जनवरी को हुआ उपद्रव आंदोलन की कमान संभाले लोगों की नाकामी है। वह अपनी मांग को लेकर सरकार से बात करने आए हैं। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। हरियाणा से आए राजेश ने बताया कि 26 जनवरी के बाद सिंघु बॉर्डर पर शुक्रवार को भी हिंसा हुई। ये सब डराने वाला है, जो भी हिंसा कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए। घर वापस जाने के लिए स्वजन का दबाव पहले से ही है। लोकतंत्र में मुद्दों पर विरोध एक सामान्य बात है, लेकिन इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है।

संपादकीय

नेपाल को संदेश और सहयोग

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञावाली काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल पर शनिवार को जैसे ही उतरे, पत्रकारों का सबसे पहला सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मिले क्यों नहीं? ज्ञावाली ने इसका जवाब न देकर 15 जनवरी, 2021 को भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक में क्या कुछ हुआ, उसकी प्रमुख बातें बताकर पत्रकारों से पीछा छुड़ाया। नेपाली विदेश मंत्री ने यह जरूर जोड़ा कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मैं मिला, और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के साथ कालापानी पर भी मैंने नेपाल का पक्ष रखा। इतना बयान दे देने भर से यह विषय नेपथ्य में नहीं गया है। विक्रम और वेताल की तरह बात वहीं आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी मिले क्यों नहीं? नेपाली अखबारों के संपादकीय, वहां का सोशल मीडिया, समवेत स्वर में यह टिप्पणी कर रहे हैं, '21 अगस्त, 2019 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जब पांचवीं बैठक के वास्ते काठमांडू आए थे, तब प्रधानमंत्री ओली से भेंट हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने समय न देकर नेपाल के राष्ट्राभिमान को आहत किया है।' इससे यही प्रतीत होता है कि सातवीं बैठक काठमांडू में हुई, तो वहां के राष्ट्रवादियों का प्रयास होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारतीय विदेश मंत्री को मिलने का समय न दें। लेकिन क्या यह प्रोटोकॉल का अनिवार्य हिस्सा है कि नेपाली विदेश मंत्री संयुक्त बैठक के वास्ते पधारें, तो प्रधानमंत्री से मिलें ही? इसे कूटनीतिक शिष्टाचार का निर्वाह कह लीजिए कि प्रधानमंत्री विदेश से पधारे बड़े नेताओं से मिल लेते हैं। 23 साल से मुर्दा पड़े इस संयुक्त आयोग को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के रहते फिर से जिंदा किया गया था। सुषमा स्वराज और उनके तत्कालीन समकक्ष महेंद्र बहादुर पांडे ने काठमांडू में 26 जुलाई, 2014 को पहली 'जेसीएम' अर्थात ज्वॉइंट कमीशन मीटिंग की थी। मोदी काल में भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठकों को पुनर्जीवित करना अच्छा फैसला था, जिससे दोनों पक्षों की शंकाओं के निवारण और सहयोग के नए आयाम ढूंढ़े जाते हैं। इस समय नेपाल को तत्काल कोविड वैक्सीन की आवश्यकता है। भारत से वैक्सीन नेपाल पहुंच जाएं, तो इसे विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञावाली को अपनी दिल्ली यात्रा की उपलब्धि माननी चाहिए। 15 जनवरी, 2021 की बैठक में स्वयं विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञावाली ने कोविशील्ड व कोवैक्सीन के लिए भारत को बधाई दी है, और वह वैक्सीन की एक करोड़ 20 लाख डोज भेजने का आग्रह कर गए हैं। उधर चीन भी नेपाल में वैक्सीन कूटनीति खेलने के प्रयास में है। ज्ञावाली यह भी प्रस्ताव दे गए हैं कि नेपाल को इसके निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए। भारत को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। संयुक्त आयोग की बैठक में ज्ञावाली के साथ उपस्थित विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला, उनके नेपाली समकक्ष भरत राज पौडेल ने कनेक्टिविटी, अर्थ-व्यापार, ऊर्जा, तेल और गैस, जल संसाधन, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मोतिहारी से अमलेखगंज तक पेट्रोलियम पाइपलाइन को चितवन तक विस्तार देने, इससे इतर पूर्वी क्षेत्र में सिलीगुड़ी से झापा तक ऐसी ही पाइपलाइन लगाने पर चर्चा हुई। जयनगर से नेपाल के कुर्था तक बड़ी रेल लाइन लग जाने से इस इलाके का कायाकल्प होना है, इसे नेपाली पक्ष भी महसूस करता है। रक्सौल से काठमांडू ब्रॉड गेज रेल पर यदि काम शुरू होता है, तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए। साझा बैठक में पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट बनाने, ऐतिहासिक पाटन दरबार का भंडारखाल बगैचा के कायाकल्प समेत पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुश्किल यह है कि नेपाली मीडिया का पूरा ध्यान नकारात्मक खबरों पर केंद्रित रहा है। वहां इस बात की खोज होती रही कि कालापानी-लिपुलेख मुद्दे को विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञावाली ने कितने पुरजोर तरीके से उठाया, और भारतीय पक्ष की ओर से क्या उत्तर मिला? मगर, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बैठक पर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें कालापानी-लिपुलेख की चर्चा नहीं है। ज्ञावाली शायद ऐसा सोचकर दिल्ली आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इस विषय पर चर्चा करूंगा। संभवत- यही वह बिंदु है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भेंट को टाल गए। नेपाल के लिए यह राजनीतिक संक्रमण काल है। संसद भंग है और सड़क पर शीर्ष नेता हिसाब-किताब कर रहे हैं। प्रचंड ने आरोप लगाया कि ओली की कुरसी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से टिकी हुई है, वरना वह निपट गए होते। ऐसे संदेह वाले माहौल में नरेंद्र मोदी का ज्ञावाली से न मिलना, कूटनीतिक विवेक और गंभीरता को ही दर्शाता है। कालापानी-लिपुलेख से भी बड़ा विषय भारत-नेपाल के बीच 1950 की संधि को बनाए रखना है। ओली और प्रचंड का राष्ट्रवाद समय-समय पर इस विषय को लेकर जगता रहा है। इसमें पलीता लगाने में भूगोलवेत्ता, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर हर्क गुरूंग की बड़ी भूमिका थी। 23 सितंबर, 2006 को गुरूंग हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, मगर अपने जीवनकाल में यह निष्कर्ष दे गए कि 1950 संधि की धाराएं बदली जाएं। नेपाली कम्युनिस्टों को आपत्ति 1950 संधि के अनुच्छेद 2 पर है, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता की चर्चा है, अनुच्छेद 5 को बदलकर नेपाल तीसरे मुल्क से हथियारों का अबाध आयात चाहता है, अनुच्छेद 6 में आर्थिक बाध्यताएं हैं, और अनुच्छेद 7को संशोधित करने के बाद भारतीय मूल के लोग वर्क परमिट के आधार पर ही नेपाल में काम कर सकेंगे। इन अनुच्छेदों में बदलाव दोनों देशों के नागरिकों के लिए परेशानियों से भरा होगा। 1950 की संधि को दुरुस्त करने के वास्ते, जुलाई 2016 में भारत-नेपाल के प्रसिद्ध लोगों का आठ सदस्यीय समूह बना, जिसका नाम रखा था ईपीजी (इमीनेंट पर्सन्स ग्रुप)। नेपाल की ओर से इस समूह के संयोजक हैं राजदूत भेख बहादुर थापा और भारत में भगत सिंह कोश्यारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 'ईपीजी' की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, मगर नेपाली मीडिया पूरे विश्वास से कह जाता है कि भारत 1950 की संधि बदलने को तैयार है। ईपीजी की अवधि 2018 में पूरी हो गई, पर प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है।

प्रवीण कुमार सिंह

हिंदी कहानी समय के साथ चल नहीं पा रही है और पिछड़ती नजर आ रही

फिल्मों में संवाद की भाषा बदलती है, गानों के बोल बदलते हैं। विकी डोनर, पीकू, दम लगाके हईसा, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेज रिकी बहल से लेकर गली बॉय तक पहुंचती है। इस बदलाव को लोगों ने पसंद भी किया और फिल्में हिंट भी हुईं। सार्त्र के शब्द उधार लेकर अगर कहें तो इन फिल्मों को 'पब्लिक' भी मिली। हिंदी कहानीकारों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो समय के साथ चलें और उन पाठकों का ध्यान रखें जहां तक उनकी रचनाएं पहुंच सकती हैं।

इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक समाप्त हो गया और अब हम तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। रचनात्मक लेखन में भी इन दो दशकों में कई बदलाव देखने को मिले। कुछ लेखकों ने अपनी कहानियों में या उपन्यासों में नए प्रयोग किए, भाषा के स्तर पर भी और कथ्य के स्तर पर भी। बावजूद इसके हिंदी में साहित्य के जितने पाठक होने चाहिए वो नहीं हैं। कहानी, कविता, उपन्यास से लेकर आलोचना और निबंध आदि की पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं। कई बार ये कहा जाता है कि पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े जानने का कोई वैज्ञानिक तरीका हमारे पास नहीं है इस वजह से ये भ्रम बनता है। हो सकता है कि इसमें सचाई हो लेकिन अगर पुस्तकों की बिक्री होती है तो इसके संकेत तो मिलने ही लगते हैं। सुरेन्द्र वर्मा के उपन्यास 'मुझे चांद चाहिए' का उदाहरण दिया जा सकता है। खैर ये अलग विषय है जिसपर फिर कभी चर्चा होगी।

अभी हम बात कर रहे हैं कि हिंदी में कहानियों या उपन्यासों के लेखन प्रविधि में कोई बदलाव हुआ या नहीं। भाषा के स्तर पर कोई नया प्रयोग हुआ कि नहीं। अगर हम सबसे पहले कहानी की बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदी कहानी की दुनिया बहुत नहीं बदली। हिंदी कहानी समय के साथ चल नहीं पा रही है और पिछड़ती नजर आ रही है। आज के ज्यादातर कहानीकार अब भी बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में लिखी गई कहानियों के विषय से अलग जाकर कोई नवोन्मेष करते नहीं दिख रहे। हिंदी की कहानियां गावों से मुक्त नहीं हो पाई है। हिंदी कहानी गांव की भाषा से भी कहां मुक्त हो पाई है। जब हम हिंदी कहानी के कम होते पाठक की बात करते हैं तो तमाम साहित्यिक गुणों और अवगुणों की चर्चा करते हैं

लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हिंदी के कहानीकार ऐसे दोष का शिकार हो रहे हैं जिसको रेखांकित किया जाना आवश्यक है। हिंदी के कहानीकार अब भी गांव भी भाषा लिख रहे हैं जबकि कहानी की पहुंच शहरी पाठक तक अधिक है। ज्यादातर कहानियां गांव की पृष्ठभूमि पर लिखी जा रही हैं जबकि उनकी पहुंच शहरी पाठकों तक अपेक्षाकृत अधिक है। हिंदी के ज्यादातर कहानीकार अपनी कहानियों में अपने पात्रों को उन घटनाओं और परिस्थियों से मुठभेड़ करवाते हैं जो गांव की होती हैं। शहरी घटनाओं और शहरी परिस्थितियों को चित्रित करने का हुनर अभी हिंदी के कम कहानीकारों के पास है।

परिणाम ये होता है कि शहरी पाठक गांव की भाषा और परिस्थितियों या घटनाओं से अपना तादात्म्य नहीं बना पाता है और वो हिंदी कहानी से विमुख होने लगते हैं। शहरी पाठक को इस वजह से रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि साहित्यिक कृतियों की पहुंच गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक है। गांवों और कस्बों में पुस्तकों की दुकानें कम हो रही हैं, कम तो शहरों में भी हैं लेकिन शहरी इलाकों में ऑनलाइन या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस कमी को बहुत हद तक पूरा कर देते हैं। हिंदी के कहानीकारों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदी के कुछ कहानीकारों ने शुरुआती कहानियों में शहरी परिवेश को उठाया लेकिन फिर वो गांव चले गए। हिंदी कहानी की इस स्थिति को देखते हुए मुझे फ्रांसीसी कथाकार सार्त्र का एक कथन याद पड़ता है। सार्त्र ने कभी कहा था कि वो एक ऐसे लेखक हैं जिनको इस बात की चिंता है कि उनके पाठक तो हैं पर पब्लिक नहीं है। सार्त्र अपने पाठकों से आगे जाकर अपने लिए जनता की तलाश करते हैं उसके लिए प्रयत्न करते हैं। लेखन के स्तर पर भी और पाठकों से आत्मीयता बढ़ाने के अन्य काम करते हुए भी। लेकिन हिंदी के कहानीकार अपने पाठकों की ही बहुत अधिक चिंता नहीं करते हैं तो उनसे ये अपेक्षा करना, कि वो अपनी रचनाओं के लिए 'पब्लिक' की तलाश करेंगे, व्यर्थ है। यही हाल हिंदी के उपन्यासों का भी है। जहां तक उपन्यासों की पहुंच है वहां की भाषा में उपन्यास कम लिखे जा रहे हैं। हिंदी के पाठक हैं, वो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उनको उनकी पसंद की सामग्री नहीं मिल पाती है। आज भी हिंदी में लिखे जा रहे अधिकांश उपन्यासों की कथावस्तु या उसकी भाषा काफी पुरानी हो गई है। हिंदी उपन्यास भी हिंदी कहानियों की तरह गांव से बाहर नहीं निकल पा रही है। उपन्यासों में गांव में आ रहे बदलावों को रेखांकित नहीं किया जा रहा है।

समकालीनता की हिंदी में बहुत बातें होती है लेकिन लेखन को समकालीन बनाने के लिए वैसे विषय नहीं उठाए जाते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से शहरों में काम करनेवाले लोग अपने गांव की ओर लौटे, उसने गांव का पूरा समीकरण बदल दिया। पारिवारिक से लेकर सामाजिक संरचना पर असर पड़ा लेकिन हिंदी कहानी या हिंदी उपन्यास इस बदलाव को अबतक नहीं पकड़ पाई है। इसके पहले की सामाजिक घटनाओं को भी समकालीन हिंदी रचनाशीलता में स्थान नहीं बना पाई है। दो चार लेखक लिखते तो हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। यह अनायास नहीं है कि हिंदी में विभाजन पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, न ही उसकी त्रासदी पर और ना ही उसके सामाजिक असर पर। यशपाल और भीष्म साहनी ने लिखा जरूर पर इतनी बड़ी त्रासदी के लिए वो बहुत कम है। भारत का विभाजन मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। इस बात पर हिंदी के साहित्यकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि समय को पकड़ पाने और उसको अपनी रचनाओं में उतार पाने में वो क्यों पिछड़ जा रहे हैं। इक्सीवीं शताब्दी के दूसरे दशक में हिंदी में कुछ नए लेखक आए जिन्होंने अपनी रचनाओं में शहरी युवाओं की कहानियां उनकी भाषा में लिखीं। पाठकों ने ऐसे लेखकों को पसंद भी किया। उनके उपन्यासों को लेकर साहित्य जगत में चर्चा भी हुई लेकिन वो अपनी ही बनाए खांचे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए और खुद को दोहराने लगे। विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर निकलते ही उनके लेखन की सीमाएं सामने आ गईं।

इससे इतर अगर हम देखें तो सिनेमा ने बदलते हुए समय को पकड़ा। जब व्यवस्था से विद्रोह की बात थी तो एंग्री यंग मैन आया। जब देश में उदारीकरण की आहट सुनाई देने लगी तो तो हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन की जगह ऐसे नायक ने ले ली जो कॉलेज का छात्र है। उसके अपने सपने हैं, वो अपने फैसले खुद लेना चाहता है। फिर जब हिंदी सिनेमा इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करता है तो उसकी कहानियां फिर बदलती हैं और वो शहरों की यथार्थवादी कहानियों तक आता है। समाज में प्रचलित उन मुद्दों पर फिल्में बनने लगती हैं जिसपर कम बात होती थी। फिल्मों में संवाद की भाषा बदलती है, गानों के बोल बदलते हैं। विकी डोनर, पीकू, दम लगाके हईसा, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेज रिकी बहल से लेकर गली बॉय तक पहुंचती है। इस बदलाव को लोगों ने पसंद भी किया और फिल्में हिंट भी हुईं। सार्त्र के शब्द उधार लेकर अगर कहें तो इन फिल्मों को 'पब्लिक' भी मिली। हिंदी कहानीकारों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो समय के साथ चलें और उन पाठकों का ध्यान रखें जहां तक उनकी रचनाएं पहुंच सकती हैं।

किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता चिंता का कारण

कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में खालिस्तानी तत्वों का सक्रिय होना चिंताजनक है। यह चिंता तबसे और बढ़ी है जबसे अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि इस आंदोलन में प्रतिबंधित खालिस्तानी तत्वों ने घुसपैठ कर ली है। उन्होंने यह बात तब कही जब कंर्सोटियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने यह आरोप लगाया कि सिख फॉर जस्टिस नामक प्रतिबंधित संगठन विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से हलफनामा पेश करने को कहा। पता नहीं इस हलफनामे में क्या होगा, लेकिन यह एक तथ्य है कि बीते करीब 50 दिनों में खालिस्तानी तत्व किसानों के बीच घुसपैठ करते दिखे हैं। इसके अलावा दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच खालिस्तानियों ने कई देशों में भारतीय दूतावासों के सामने प्रदर्शन किया है।

किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी तत्वों की नए सिरे से सक्रियता इसलिए चिंता का कारण है, क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी गतिविधियां पहले से जारी हैं। खालिस्तानी तत्वों को खाद-पानी देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की शह पर ही एक अर्से से कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में बैठे खालिस्तानी तत्व इंटरनेट मीडिया पर 2020 में अलग खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराने का अभियान चला रहे थे। इसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनकी गतिविधियां अब भी जारी हैं। खालिस्तानी विदेश में रह कर पंजाब में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने का काम करते हैं। हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में आतंकी गतिविधियों के मामले में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा हाल में दुबई से डिर्पोट किए गए खालिस्तानी आतंकी सुखी बिकरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग कराता था। ऐसे कुछ तत्व ब्रिटेन और कनाडा में भी हैं। उन पर पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं पर हमले कराने के आरोप हैं।

खालिस्तानियों का पाकिस्तान से पुराना गठजोड़ है। खालिस्तानी यह देखने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान में किस तरह सिख लड़कियों को उसी तरह अगवा किया जा रहा है, जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि खालिस्तानी उस पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए हैं, जहां सिखों का जीना मुहाल है। वे उस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने का प्रविधान रखता है। खालिस्तान समर्थकों के वैचारिक दिवालियापन के ऐसे तमाम उदाहरण हैं।

पाकिस्तान ने भारत से घृणा के चलते अपनी एक मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा है। अब्दाली ने 18वीं शताब्दी में भारत पर कई हमले कर भीषण नरसंहारों को अंजाम दिया था। इनमें मथुरा, वृंदावन और अमृतसर में किए गए जनसंहार भी शामिल हैं। अब्दाली ने स्वर्ण मंदिर को दो बार गिराया और पवित्र अमृत सरोवर को गायों को काट कर भरा। पांच फरवरी, 1762 को अब्दाली ने हजारों की संख्या में सिखों का नरसंहार कराया, जिसमें अधिकतर स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध थे। यह पंजाब के इतिहास में वड्डा घल्लूघारा के नाम से जाना जाता है। यह शर्म की बात है कि खालिस्तानी इसी अब्दाली को अपना राष्ट्रीय नायक मानने वाले पाकिस्तान से हाथ मिलाए हुए हैं और उसकी कठपुतली बने हुए हैं। दरअसल इस रोग की जड़ें कहीं अधिक गहरी और पुरानी हैं। अंग्रेजों ने जब बांटो और राज करो की नीति को लागू किया तो भारतीय समाज में तरह-तरह से फूट डालने के प्रयास किए।

ये प्रयास सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी थे। इसके भारतीय जनमानस पर दूरगामी प्रभाव हुए। सिखों को हिंदू समाज के विरुद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने एक ईसाई पादरी सर जॉन अर्थर मैकालिफे को सिख इतिहास लिखने के काम पर लगाया। मैकालिफे ने सिखों में सुनियोजित तरीके से यह भ्रांति फैलाई कि सिख दर्शन दरअसल इब्राहिमी धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाइयत के अधिक करीब है, न कि हिंदू धर्म के। यह इसलिए किया गया, ताकि सिखों का अंग्रेजीकरण करके उन्हें ईसाइयों और मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया जा सके। 1857 के बाद का ब्रिटिश आकलन यह था कि अगर भविष्य में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसे कुचलने के लिए सिख और मुस्लिम दस्तों का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि इन छोटे अल्पसंख्यक समुदायों से ब्रिटिश सेना अकेले भी निपट सकती है। इस ब्रिटिश चालबाजी के चलते सिख समुदाय को बड़ा झटका 1947 में लगा, जब मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के साथ-साथ सिख समुदाय का भी भीषण नरसंहार किया और पश्चिमी पंजाब से लाखों की संख्या में सिखों को सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस जनसंहार और मानवीय त्रासदी की कहानी 1950 में खुद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 'मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन द पंजाब 1947' के नाम से प्रकाशित कर चुका है।

लोकतांत्रिक कशमकश

संयोग ही कहिए कि आसियान के सदस्य और हमारे पड़ोस के दो दक्षिण-पूर्व एशियाई मुल्क थाईलैंड और म्यांमार अभी लोकतंत्र को लेकर गजब की कशमकश से गुजर रहे हैं। एक देश के लोगों में राजशाही की निरंकुशता से मुक्ति पाकर लोकतांत्रिक शासन का स्वाद चखने की बेकरारी दिख रही है तो दूसरे देश में लोकतंत्र को लेकर जारी सीमित प्रयोगों पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। थाईलैंड में पिछले करीब एक साल से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के निशाने पर शुरू में प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ही थे, लेकिन धीरे-धीरे लोगों के असंतोष का दायरा बढ़ता गया और राजशाही से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव भी आंदोलन के अजेंडे में शामिल हो गया। वहां राजपरिवार की सार्वजनिक आलोचना के खिलाफ बेहद कड़ा कानून है, जिसके इस्तेमाल की नौबत आम तौर पर नहीं आती है। लेकिन पिछले नवंबर महीने से प्रदर्शनकारियों पर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है और इस महीने एक 63 वर्षीया महिला अंचन को इस कानून के तहत 43 साल कैद की सजा सुना दी गई। नाबालिग छात्रों की गिरफ्तारी से भी लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। नतीजा यह कि कोरोना के मामले अचानक बढ़ जाने के चलते दिसंबर महीने से सड़कों पर प्रदर्शन का जो सिलसिला थम-सा गया था, वह फिर से शुरू हो गया है।

उधर म्यांमार में बीते नवंबर में हुए चुनावों में लोगों ने आंग सान सू की को पहले से भी बड़ा बहुमत दिया, लेकिन यही बात वहां लोकतंत्र के लिए खतरा बनती दिख रही है। आलम यह है कि आज, यानी 1 फरवरी, दिन सोमवार से नवनिर्वाचित संसद की बैठक शुरू होने वाली है लेकिन देश में यह अफवाह फैली हुई है कि सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी। म्यांमार के संविधान के मुताबिक संसद की एक चौथाई सीटें सेना के लिए आरक्षित रहती हैं, जिन पर सैन्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा वहां सेना समर्थक दल अलग से भी चुनाव लड़ते हैं। नतीजा यह कि निर्वाचित सरकार पर सेना का अंकुश लगातार बना रहता है। इस बार आंग सान सू की को मिले शानदार बहुमत ने निश्चित रूप से उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया है। लेकिन सेना कह रही है कि चुनावों में धांधली हुई है जबकि चुनाव आयोग के मुताबिक उसे इस धांधली के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के बयानों के बाद देश में यह अफवाह फैली कि सेना विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा करने वाली है।

दिलचस्प यह कि सेना के प्रवक्ता ने इन अफवाहों का खंडन करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दूतावास और 15 देशों के डिप्लोमैटिक मिशन की तरफ से बाकायदा बयान जारी कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी भी तरह के खिलवाड़ के खिलाफ आगाह किया गया। आम राय यह है कि सेना इस बयान की गंभीरता को समझेगी। बहरहाल, दुनिया यही चाहेगी कि चाहे म्यांमार हो या थाईलैंड, दोनों देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो और जनमत का सम्मान किया जाए।

कोरोना काल में महामारी से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा को मिली नई पहचान

जूस का मतलब अभी तक केवल फ्रूट जूस होता था, लेकिन अब उनका स्थान आंवला, गिलोय, एलोवेरा और तुलसी जैसे जूस ने ले लिया है। इसके अलावा काढ़ा भी लोगों की जळ्बान पर ऐसा चढ़ा कि संक्रमण काल में राष्ट्रीय पेय बन गया। इससे लोग न केवल संक्रमण से बचे, बल्कि मौसमी बुखार, जुकाम और सर्दी से भी बचे। इलाज से बेहतर रोकथाम है और यह आयुर्वेद का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह केवल विकल्प नहीं, बल्कि चिकित्सा का मुख्य आधार है जो मानवजाति को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के वायरस से बचा सकता है।

कोरोना से निपटने के लिए दो स्वदेशी टीकों का निर्माण कर भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया, जिन्होंने टीके का निर्माण किया है। इससे भारतीय वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को भी हासिल किया जिस पर हरेक भारतीय को गर्व होना चाहिए। भारत न केवल टीका बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि इस मामले में दूसरे देशों का भी मददगार बनेगा। जनसंख्या के लिहाज से दुनिया की 18 फीसद आबादी वाले भारत ने बाकी देशों की तुलना में अपनी परंपरागत या मूल चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के बल पर न केवल महामारी के संकट से लंबे काल तक निपटा, बल्कि इसकी बदौलत बाकी देशों की तुलना में औसत मृत्यु दर डेढ़ प्रतिशत से भी कम रखने में सफल रहा। भारत ने यह भी साबित किया कि प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने पर हर तरह के वायरस से बखूबी निपटा जा सकता है। कोरोना से निपटने में भारतीय चिकित्सा पद्धति के सफल प्रयासों की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है।

यह विशेष योग है कि 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। योग और आयुष उनके एजेंडे में थे। सबसे पहले उन्होंने योग को न केवल देश, बल्कि दुनिया में व्यवहार के स्तर पर सिरे से पहचान दिलाने में सफलता हासिल की। कहा जाता है योग के पीछे-पीछे आयुर्वेद अपने आप चला आता है। योग दिवस के एलान के डेढ़ महीने बाद भारत

सरकार ने आयुष विभाग का दायरा बढ़ाकर उसे आयुष मंत्रालय का दर्जा दिया। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल हैं। इस मंत्रालय ने कोरोना संकट से निपटने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा और उसने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना। इस केंद्र के स्थापित होने के बाद दुनिया में भारत की चिकित्सा पद्धति को नई पहचान मिलेगी।

दुनिया की एक विशाल आबादी भारत में रहती है और विकसित देशों की तुलना में यहां स्वास्थ्य का ढांचा भी उतना विकसित नहीं है। ऐसे में कई विशेषज्ञ यह आशंका जता रहे थे कि भारत में करोड़ों व्यक्ति कोरोना संक्रमण के दायरे में होंगे और कई लाख मौत के शिकार होंगे। इन आशंकाओं ने देश को अंदर तक हिला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस संकट की गंभीरता को शायद पहले से भांप रखा था। तभी उन्होंने सख्त लॉकडाउन के एलान के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की। प्रधानमंत्री की पहल पर आयुष मंत्रालय ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले नुस्खों और औषधियों का जमकर प्रचार किया। किसी महामारी से निपटने में सरकारी तौर पर पहली बार आयुर्वेद और योग को इलाज के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल भी जारी किया।

कोरोना संक्रमण से उपजे संकट के कारण परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए नए-नए शोध होने लगे हैं, ताकि भविष्य के संकट का मुकाबला करने की तैयारी रखी जा सके। इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर, 2020 को देश को दो आयुर्वेद संस्थान समर्पित किए-आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर। दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने शोध में पाया है कि आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि अश्वगंधा में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिनमें अद्भुत प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। संक्रमण काल में लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर आयुष मंत्रालय आयुर्वेद दवाओं को लेकर कई स्तर पर लगातार सर्वे भी करता रहा। मसलन दिल्ली पुलिस के करीब 80 हजार जवानों को मंत्रालय की तरफ से आयुष किट दी गई। उनमें कोरोना संक्रमण नहीं के बराबर हुआ, लेकिन इसके मुकाबले किट न पाने वाले जवानों में संक्रमण आठ गुना ज्यादा था। इसके साथ मंत्रालय ने करीब डेढ़ लाख लोगों पर एक सर्वे और किया जो किसी न किसी रूप में अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई न कोई आयुर्वेदिक औषधि ले रहे थे। इससे उनका बचाव हुआ और अगर संक्रमण हुआ भी तो उसकी तीव्रता काफी कम थी। दुनिया के अलग-अलग देशों ने कोरोना पर लगाम लगाने के अनेक प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन उनके मुकाबले भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपेक्षा से कहीं ज्यादा सफल रही।

कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद के उत्पादों की बिक्री करीब छह गुना बढ़ गई है। इस दौरान करीब दो सौ नए उत्पाद बाजार में आए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश है। संक्रमण काल में पूरे साल इसकी मांग कम नहीं हुई। इसी तरह गिलोय, तुलसी, हल्दी और अश्वगंधा ने भी मांग के नित नए रिकॉर्ड कायम किए। जूस का मतलब अभी तक केवल फ्रूट जूस होता था, लेकिन अब उनका स्थान आंवला, गिलोय, एलोवेरा और तुलसी जैसे जूस ने ले लिया है। इसके अलावा काढ़ा भी लोगों की जळ्बान पर ऐसा चढ़ा कि संक्रमण काल में राष्ट्रीय पेय बन गया। इससे लोग न केवल संक्रमण से बचे, बल्कि मौसमी बुखार, जुकाम और सर्दी से भी बचे। इलाज से बेहतर रोकथाम है और यह आयुर्वेद का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह केवल विकल्प नहीं, बल्कि चिकित्सा का मुख्य आधार है जो मानवजाति को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के वायरस से बचा सकता है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के 46 हजार गांव, जानिए, राज्य को क्या मिला और कहां मिली निराशा

पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया। इसमें राज्य के सभी 45945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात है। बिहार के अर्थशास्त्री डॉ. नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को स्पेशल पैकेज की उम्मीद थी। बजट में रोजगार व आयकर में राहत के क्षेत्रों में भी निराशा हाथ लगी है। आइए नजर डालते हैं बिहार को क्या मिला खास और वो कौन सी उम्मीदें हैं, जो पूरी नहीं हो सकीं। बजट बिहार में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उम्मीद जगाता है। बिहार की बात करें तो राज्य के 45945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार ने बीते 21 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। बिहार की नीतीश सरकार कई साल से राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जा की करती रही है। बजट में इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.65 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। उसकी बहुत सारी राशि पहले ही मिल चुकी है, लेकिन शेष राशि के लिए घोषणा का भी इंतजार था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। उस वक्त से इस मांग के पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है। इस बजट में भी इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। अमृतसर-हावडा इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के निर्माण की घोषणा की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। इस कॉरीडोर के बनने से बिहार के औरंगाबाद, गया व कैमूर सहित छह जिलों को फायदा होता। दिल्ली व मुंबई की तरह विदेशी कंपनी के सहयोग से बिहार में भी उद्योग के लिए डेडिकेटेड कॉरीडोर की सुविधा देने की उम्मीद थी। बजट इसपर भी मौन रहा।

इंटरनेट कॉल पर मुरादाबाद शहर विधायक को मिली धमकी, कहा-मोदी और इजरायली विदेश मंत्री की भी हत्या होगी

मुरादाबाद । मुरादाबाद नगर के विधायक भाजपा नेता रितेश गुप्ता और उनके परिवार को एक बार फिर जानमाल की धमकी दी गई है। मोबाइल इंटरनेट कॉल के जरिए मिली धमकी के बाद नगर विधायक ने गलशहीद पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस सनसनीखेज घटना के प्रकाश में आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम धमकी देने वालों की तलाश में जुट गई है। पुलिस को दिए गए तहरीर में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि + 923156267120 नंबर से उनके मोबाइल फोन पर वाट्सएप पर एक वीडियो काल आई। 31 जनवरी को सुबह 11:30 बजे कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने अभद्रता के साथ विधायक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं काल करने वालों ने प्रधानमंत्री को भी अपशब्द कहा। बीजेपी व आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाने पर बताते हुए कहा कि सूचना देने का मकसद सिर्फ यह है कि तुम लोग खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। इसके आगे फरि कहा कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट महज ट्रायल है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली विदेश मंत्री की जल्द हत्या होगी। नगर विधायक से मिली इस सनसनीखेज सूचना के बाद पुलिस महकमा हरकत में है। संबंधित मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। इस बाबत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने बताया कि नगर विधायक से तहरीर मिली है। अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर पुलिस धमकी भरे काल की जांच में जुटी है।

बिहार से दिल्ली बुलाए गए बीजेपी के बड़े नेता, सामने आ सकते हैं नीतीश कैबिनेट के नए चेहरे

पटना । नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के नए चेहरे सोमवार को सामने आ सकते हैं। इसके लिए बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। बिहार से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, संगठन महामंत्री नाग्रेंद्र नाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता देश की राजधानी रवाना हो चुके हैं। संसद सत्र के चलते पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पहले से ही दिल्ली में हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार फरवरी के पहले हफ्ते में ही नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। नीतीश कुमार कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के करीब 12 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसमें कई के नाम पहले तय माने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का नाम सबसे आगे है। सात बार के एमएलसी नवल किशोर यादव की भी चर्चा मंत्री बनाने को लेकर है। वहीं पूर्व मंत्री और मिथिलांचल से आने वाले भाजपा उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अंग प्रदेश के रहने वाले बिहपुर से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र भी नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। भाजपा का युवा चेहरा नितिन नवीन को मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व मंत्री प्रेमकुमार की जगह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी को मंत्री बनाने की चर्चा है। मुंगेर के रहने वाले और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को भी पार्टी मंत्री बना सकती है। इस बीच चंपारण क्षेत्र से राणा रणधीर के नाम की भी चर्चा जोरों पर है।

जगराओं में 78 बोतल अवैध शराब व 1000 लीटर लाहन समेत दो गिरफ्तार

जगराओं, (लुधियाना) । थाना सदर और थाना सिधवांबेट पुलिस टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 78 बोतल शराब और 1000 लीटर लाहन बरामद की है। पुलिस ने गांव काउंके खोसा में रेड कर विक्रमजीत सिंह को 58 बोतल शराब फर्स्ट च्वाइस सेल हरियाणा भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित हरियाणा से सस्ते दाम पर शराब लाकर अपने गांव में बड़े स्तर पर बेचता है। बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ थाना सदर जगराओं में एक्साइज एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं थाना सिधवांबेट पुलिस ने हवलदार गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में बस अड्डा चौक गांव काकड तिहाडा में नाकाबंदी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि परमजीत सिंह पम्मा सतलुज दरिया के नजदीक जमीन गांव बहादरके में लाहन डालकर अवैध शराब निकाल बेचने का धंधा करता है। इस समय भी गांव में शराब निकालने के लिए लाहन डाली हुई है। पुलिस ने परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी गांव बहादुरके के खिलाफ थाना सिधवांबेट में एक्साइज एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज करके रेड की गई तो 20 बोतल अवैध शराब तथा 1000 लीटर लाहन समेत परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद की गई लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपितों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह कितने दिन से यह धंधा कर रहे हैं।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ट्रैकिंग ट्रेल पर चलाया जागरूकता अभियान

देहरादून । उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) की ओर से रविवार को ट्रैकिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। शहंशाही आश्रम से झड़ीपानी तक करीब पांच किलोमीटर के ट्रैकिंग ट्रेल के अनुरक्षण, साफ-सफाई आदि कार्य के लिए सहभागिता को स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया गया। शहंशाही आश्रम से झड़ीपानी के पैदल ट्रैकिंग ट्रेल के विकास और देखरेख के लिए यह पहल की जा रही है। इस ट्रैकिंग ट्रेक का विकास उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और नगर पालिका परिषद मसूरी संयुक्त रूप से करेंगी। इस दौरान पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि ट्रैकिंग ट्रेल को स्वच्छ बनाने का प्रयास है। इस दौरान ट्रैक पर चलने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण कर उनके सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि इस ट्रैक का इस्तेमाल करने वालों के लिए स्थानीय निवासियों की एक कमेटी गठित की जाएगी।

देश की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति वाला बजट : योगी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी सरकार के आम बजट को आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बताया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

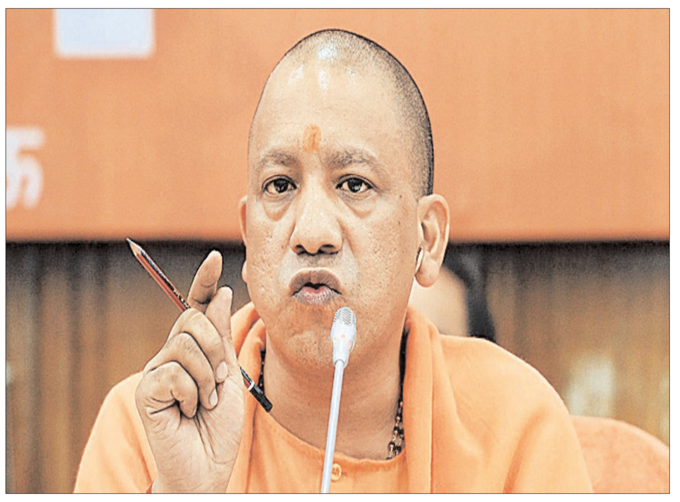

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में समाज के हर तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है वह अभिनंदनीय है। यह बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बजट है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण आज जब विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकटग्रस्त हैं, उस संक्रमण काल में इतने व्यावहारिक और विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र हैं। निस्संदेह यह बजट हम सभी भारतीयों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न हर हाथ को काम को साकार करता यह आम बजट सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। बजट के सभी प्रस्तावों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।

अंत्योदय की भावना को साकार करता वर्तमान आम बजट अभिनंदन योग्य है। यह नए भारत की नई अर्थनीति का प्रकटीकरण है। आज का आम बजट न केवल आम आदमी के सपने साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। वर्तमान आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है।

यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का टेक्नोलॉजी के महत्व पर ध्यान के कारण भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए वित्त मंत्री का हृदय से अभिनंदन है।

रेल बजट में उत्तर प्रदेश को मिलीं दो नई ट्रेन- नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में सोमवार को उत्तर प्रदेश को रेल मंत्रालय ने बड़ा तोहफा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पेश किया।

केंद्र सरकार के बजट में सोमवार को उत्तर प्रदेश को दो नई ट्रेन का तोहफा मिला है। इसमें से एक लखनऊ से ही चलेगी जबकि दूसरी ट्रेन असोम के जयपुर से गोमती नगर (लखनऊ) के कामाख्या से चलेगी। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

बजट में आज घोषणा की गई कि लखनऊ से जयपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन ट्रेन का संचालन होगा। यह ट्रेन लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से जयपुर के बीच चलेगी। इसका संचालन पांच फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सप्ताह में अब एक बार उदयपुर शहर के लिए लखनऊ से कामाख्या के बीच संचालित होने वाली एक और ट्रेन आठ फरवरी से शुरू होगी।

नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट में इस बार अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की सौगात भी दी गई है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत अभियान को गति मिलेगी। कोरोना के कारण जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है, उस संक्रमण काल में इस बजट को ऐतिहासिक, व्यावहारिक और विकासोन्मुखी बजट बताया जा रहा है। वर्तमान आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप बताया जा रहा है।

कन्नौज के युवक ने लखनऊ में विधान भवन के सामने खुद को लगाई आग, सीसी फुटेज में कैद हुआ दर्दनाक का मंजर

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधान भवन के सामने सोमवार को हड़कंप मच गया। कन्नौज से पहुंचे एक युवक खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाकर ने आत्मदाह का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह है कि विधान भवन के बाहर आत्मदाह की घटनाएं रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। बावजूद इसके पुलिसकर्मी इस घटना को नहीं रोक सके।

दरअसल, मूलरूप से कन्नौज के इंदरगढ़ मुंदारा निवासी रामसरन के बेटे उमाशंकर सोमवार को रोडवेज बस से लखनऊ आए थे। इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ल के मुताबिक, चारबाग बस स्टेशन पर उतरने के बाद उमाशंकर पैदल ही विधान भवन की तरफ आया था। उमाशंकर ने जेब में एक बोतल रखी थी, जिसमें पेट्रोल था। विधान भवन के पास आकर उमाशंकर ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और उमाशंकर को सिविल अस्पताल ले जाया गया। आग से उमाशंकर 30 फीसद झुलस गए हैं। वहीं, विधान भवन के बाहर लगे सीसी फुटेज में दर्दनाक मंजर कैद हो गया। लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप- पीड़ित उमाशंकर ने बताया कि जमीन विवाद में वह भागदौड़ करके परेशान हो चुका हैं। स्थानीय लेखपाल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हजरतगंज पुलिस यह पता लगा रही है कि उमाशंकर के साथ कोई और भी लखनऊ आया था या नहीं।

चौथी महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़, जयंत चौधरी पहुंचे

बिजनौर । मुजफ्फरनगर और बागपत की सफलता के बाद आज बिजनौर में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में कई शहरों से किसान भारी संख्या में जुट गए हैं। साथ ही अन्य किसान भी अपने साधन और ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। इसके अलावा कई नेताओं का भी जमावड़ा हुआ है। इस महापंचायत को भाकियू राष्टीय अध्यक्ष नरेश टिकैत व रालोत नेता जयंत संबोधित करेंगे। वहीं मंच पर राजनीतिक नेताओं को चढ़ने नहीं दिया गया है।

महापंचायत में नरेश टिकैत और जयंत चौधरी के इंतजार के बीच रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंच गए हैं। भकियू युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पहुंच चुके हैं। इनके अलावा अन्य नेता भी पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक नेताओं को मंच पर जगह नहीं दी गई है। सूचना मिल रही है कि जल्द ही नरेश टिकैत पहुंच जाएंगे। वहीं पुलिस भी मौजूद है, जो सुरक्षा का चारो ओर से जायजा ले रही है।

किसानों का उमड़ा सैलाब - किसान सम्मान महापंचायत में सोमवार की सुबह दस बजे से ही किसानों का आना शुरु हो गया। दोपहर एक बजे तक मैदान लगभग भर चुका था। महापंचायत में किसान संगठनों के अलावा सपा और रालोद के नेता भी शामिल हुए। हालांकि सपा के तीन विधायकों और दो पूर्व मंत्रियों को मंच पर जगह नहीं दी गई। हालांकि तीनों विधायक और पूर्व मंत्री मंच पर गए थे लेकिन, किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उन्हें आग्रह कर नीचे बैठा दिया। जिसके बाद विधायक और पूर्व मंत्री नीचे जमीन पर मंच के सामने ही बैठ गए।

कोई राजनीति पार्टी नहीं - रैली में सिर्फ यूनियन के झंडे और तिरंगा ही दिखाई दिया। दूसरी पार्टियों के पदाधिकारी बिना झंडे के शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय किसान नेताओं ने मंच संभालते हुए सरकार को किसान विरोधी नीति के चलते जमकर कोसा। एहतियात के तौर पर महापंचायत के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अन्य जिलों से भी फोर्स मंगाया गया है। आईजी रमित शर्मा जिले में कैंप किए हुए हैं।

महापंचायत के लिए तैनात रहेंगे 700 पुलिसकर्मी

किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए रूपरेखा तैयार की है। करीब 700 पुलिसकर्मी महापंचायत स्थल पर और आसपास तैनात रहेंगे। रविवार की देर शाम तक पुलिस अफसर महापंचायत के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के मंथन में लगे हुए थे। पंचायत की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 सिपाही, 200 दारोगा, 16 इंस्पेक्टर और छह सीओ लगाए गए हैं।

गोंडा डॉक्टर अपहरणकांड में एक और आरोपित गिरफ्तार, बोली- दोस्ती के जाल में फंसाकर किया था किडनैप

गोंडा । उत्तर प्रदेश के चर्चित गोंडा के एससीपीएम नर्सिंग कॉलेज के छात्र गौरव हालदार के अपहरण मामले में सोमवार को पुलिस ने एक और आरोपित महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित महिला पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। एसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सर्विलांस के माध्यम से डॉ. प्रीति मेहरा को उसके मूल आवास गांव ग्राम धौर जनपद झज्जर, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। शॉटकट से कमाने थे पैसे तो दोस्ती के जाल में फंसाकर किया किडनैप...

पूछताछ के डॉ. प्रीति मेहरा ने बताया कि शॉटकट से पैसे कमाने के लालच में अपने दोस्त डॉ. अभिषेक व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर गौरव हालदार को दोस्ती के जाल में फंसाया और गोंडा आकर उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया था। मूलरूप से हरियाणा निवासी प्रीति मेहरा पुत्री डॉ.राजेंद्र सिंह वर्तमान में दिल्ली के प्रेमनगर में रहती थी।

18 जनवरी को हुआ था अपहरण, मांगी थी 70 लाख की फिरौती- दरअसल, देवी पाटन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि चिकित्सक व दवा व्यापारी निखिल हालदार का पुत्र गौरव गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के एससीपीएम (सतीश चंद्र पांडेय मेमोरियल) कॉलेज में बीएएमएस प्रथम वर्ष का छात्र है।

छात्र इसी कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। बीते 18 जनवरी को गौरव का अपहरण हुआ था। पिता निखिल की तहरीर पर 19 जनवरी को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा किया गया था। अपहरणकर्तों ने 70 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती के लिए 22 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद निखिल की तहरीर पर गौरव के अपहरण का मुकदमा नगर कोतवाली में किया गया।

नोएडा से सकुशल बरामद छात्र- एसपी शैलेश कुमार पांडेय ने छात्र की बरामदगी के लिए छह टीमों को लगाया। साथ ही एसटीएफ को भी लगाया गया था। एसटीएफ व जिले की पुलिस के संयुक्त प्रयास से अपहरण किए छात्र को ग्रेटर नोएडा से 22 जनवरी को सकुशल बरामद कर लिया गया।

मुठभेड़ के दौरान आगरा की तरफ चढ़ने वाले जीरो पॉइंट से डॉ. अभिषेक सिंह, नीतेश पुत्र विनोद बिहारी, मोहित सिंह पुत्र शिव मूरत सिंह को गिरफ्तार कर अपहृत गौरव हालदार को बरामद कर लिया गया था। दो अन्य आरोपित रोहित सिंह निवासी बहराइच, सतीश कुमार को 23 जनवरी को संतकबीरनगर से गिरफ्तार किया गया था।

पूर्णिया पुलिस का जन सुविधा एप नहीं आ रहा लोगों के काम, चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य काम के लिए

पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस को अत्याधुनिक बनाकर लोगों को पुलिस संबंधित कार्य मोबाइल एवं कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे दी जाने वाली सुविधा ठप हो गई है। पुलिस की ओर से तैयार किया गया जन सुविधा अब लोगों के काम नहीं आ रहा है। पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से यह काम नहीं कर रहा है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एप के माध्यम से घर बैठे मिलने वाली सुविधा के लिए अब लोगों को पुलिस कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

इस कारण पुलिस कार्यालय में भी लोगों की भीड़ भी बढने लगी है। यह एप कोरोना काल में लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था। लॉकडाइन के कारण लोग अपने कार्य ऑनलाइन निष्पादित करते थे। लेकिन अब यह एप बंद होने से लोगों को ऑनलाइन तरीके से मिलने वाली सुविधा ऑफलाइन में बदल गया है।बताते चलें कि विगत दो साल पूर्व पूर्णिया पुलिस को आईएसओ सर्टिफाइड का प्रमाण पत्र मिला था। उस दौरान पुलिस की कार्यशैली में बदलाव आया था। उसी क्रम में आम लोगों से ऑनलाइन तरीके से जुडने के लिए जन सुविधा एप लांच किया गया था।

कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था शिथिल होते गया। वर्तमान में आलम यह है कि यह एप पूर्णतः काम करना बंद कर दिया है। यहां तक कि कई लोग इस एप के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज कराए थे, चरित्र का आवेदन किए थे लेकिन वह एप काम नहीं करने के कारण उनका काम नहीं हो पाया और अब वह कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। एप के माध्यम से जिला में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी का नाम और नंबर लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाता था। लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते थे और फिर फिडबैक भी देते थे।

चरित्र आवेदन करते थे, अपना सुझाव देते थे, पुलिस द्वारा आम लोगों के लिए जारी किया गया सूचना आसानी से आम लोगों तक पहुंच जाती थी। इस तरह से यह एप आम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा था।एप के माध्यम से ऑनलान तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र बनने के कारण काउंटर पर लोगों की भीड़ नहीं के बराबर लगती थी। लोग घर बैठे ही एप से आवेदन कर देते थे और समय से प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब एप ठप होने से ऑनलाइन काम बंद हो गया है जिस कारण पुलिस कार्यालय में बने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदक की भीड़ बढ़ गई है। काउंटर पर बैठे कर्मी ने बताया कि एप एक माह से काम नहीं कर रहा है जिस कारण अब लोगों को भौतिक रूप से काउंटर पर पहुंचकर आवेदन करना पड़ रहा है जिस कारण फिर से भीड़ बढ़ गई है।

सबौर का एक टोला जहां बरसात के दिनों में सड़क पर चलती है नाव, खतरे में होती है जान

भागलपुर । कमिश्नरी और जिला मुख्यालय से महज सात किलोमीटर दूर और सबौर प्रखंड मुख्यालय से दो किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सबौर मुस्लिम , हरिजन और ब्राह्मण टोला को जोड़ने वाली एक पथ जिसमें बरसात के दिनों में पांच फीट तक बाढ़ का पानी लगता है। इस मार्ग से एनएच तक पहुंचने के लिए नाव की एक मात्र सहारा रह जाती है। इस जटिल समस्या से मुक्ति पाने के लिए पीड़ित लोगों ने पंचायत के मुखिया, जिप सदस्य, विधायक और सांसद से कई बार गुहार लगा चुके हैं पर इस ओर अब तक किसी का भी ध्यान नहीं गया है।

विकास योजनाओं की धरातल पर खुल रही पोल, सब कुछ देख रही पब्लिक- नली गली और पथ निर्माण की विकास का दंभ चाहे सरकारी तंत्र जितना भर ले। लेकिन धरातल पर पथ उसके विकास की पोल खोल देती है। लंबे समय से यहां के स्थानीय लोग पथ निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि किसी की भी इस ओर नजरें इनायत नहीं होती है।

क्या कहते हैं मोहल्ले के लोग

मोहल्ले में रहने वाले मो. इंतेसार आलम, तमन्ना परवीन, अमित कुमार, सोम कुमार ,मधु तिवारी, सुमन यादव, अशोक चौबे, भागवत चौबे, टिल्लू दास, डॉ. शौकत, देवेंद्र वर्मा, वार्ड सदस्य पिंटू झा आदि कहते हैं कि सबौर पंचायत का 10 नंबर वार्ड विकास रोशनी से महरूम है। बरसों से यहां के लोग पथ निर्माण की बाट जोह रहे हैं। जबकि महज पथ की लंबाई एनएच 80 से 300 फीट के आसपास है। पथ के अभाव में बरसात के दिन में नाव से ही मुख्य पथ पर जाने का मात्र एक विकल्प होता है।

नल जल योजना की बात करें तो पीएचइडी द्वारा नल जल का काम किया गया है। जो कई जगह लिक है। जिससे कीचड़ हो जाता है। वहीं घरों में लगाए गए नलों में पानी का फोर्स इतना कम है कि लगाया गया नल शोभा का विषय वस्तु बनकर रह गया है। पथ बनाने के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने प्रखंड से जिला तक गुहार लगाई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कहा लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका इसकी कसक यहां रह रहे वाशिंदों के बीच है। एक अदद पथ का नहीं बनना सरकार के विकास की पोल खोल रही है।

रोते हुए फेसबुक पर फिर लाइव हुआ दीप सिद्धू, बताया पंजाब में अभी कहां और किस हालत मे छिपा है

चंडीगढ़ । 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किला पर हुई घटना के आरोपित पंजाबी फिल्म के एक्टर दीप सिद्धू ने एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर अपना पक्ष रखा है। लाल किले पर हुए उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू की तलाश में छापामारी कर रही है। दीप सिद्धू ने अपनी हालत के बारे में भी बताया और यह भी जानकारी दी कि वह कहां और किस हाल में है।

दीप सिद्धू ने फेसबुक पर लाइव होकर यह तो नहीं बताया कि वह पंजाब में किस जगह पर है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर दी कि कहीं खेत मजदूरों से शरण लेकर बैठा है। रविवार रात को सिद्धू एक बार फिर फेसबुक पर लाइव हुआ लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। सिद्धू ने खुलासा किया है कि वह दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद पटियाला आकर छिपा था। दो दिन पहले पटियाला पहुंच गया था लेकिन वहां किसी ने पंजाब पुलिस को सूचित कर दिया। पटियाला पुलिस ने छापेमारी भी की लेकिन कुछ लोगों और भगवान की मदद से वह वहां से बच कर निकल गया।

सिद्धू ने कहा कि वहां से निकलने के बाद उसने खेतों में काम कर रहे मजदूरों के घर में पनाह ली। केस दर्ज होने और किसान नेताओं की ओर से गद्दार कहे जाने को लेकर उसने पंजाबियों को भी ललकारा। उसने कहा, जेल जाने से नहीं डरता हूं, लेकिन वापस आकर सब को देख लूंगा। पंजाबियों से तो बिहार के लोग ही अच्छे हैं जो समझते हैं कि मैंने जो किया वह पंजाब के लिए किया। उसने रोते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने मुझे पनाह दी है और रोटी नहीं मिली तो अब केले व किन्नू खाकर गुजारा कर रहा हूं।

15 मिनट के फेसबुक लाइव में दीप सिद्धू में अपने पिता पर उंगली उठाने वाले मीडिया कर्मी को जेल से बाहर आकर देख लेने की धमकी भी दी। इसके साथ ही सनी देओल से भी कहा है कि वह भी उसका साथ छोड़ गए, जबकि चुनाव के समय उसने सनी के लिए 20 दिन तक सख्त मेहनत की है। सनी भी उसके साथ खड़ा नहीं हुए। पंजाबियों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद कोई भी पंजाबियों का साथ देने नहीं आएगा। मेरे पास एक एक बंदे का हिसाब है लेकिन आंदोलन के कारण चुप हूं। सिद्धू ने लक्खा सिधाणा को गद्दार कहने वालों की भी आलोचना की।

एक नजर

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चार साल पहले पत्नी के हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

उदयपुर । चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी क्षेत्र में चार साल पहले पत्नी की हत्या के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन सूत्रों के अनुसार बोहेड़ा भीलवाड़ा निवासी गुलाबंचद को भादंसं की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

बताया गया कि बीएसएल में सेवारत गुलाबचंद ने 17 मई 2016 में अपनी पत्नी सन्नो की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। जिसके खिलाफ उनके साले जमनालाल ने बड़ीसादड़ी थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बहन सन्नो बहनोई गुलाबचंद तथा भांजी अंशिका के साथ बोहेड़ा में किराए के मकान में रहता था। सत्रह मई को उनके पास फोन आया कि उनके बहनोई ने उनकी बहन की हत्या कर दी और शव मकान में पड़ा है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपनी बहन का शव देखा, जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अदालत में 11 गवाह तथा 24 दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों में चली बहस के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय निम्बाहेड़ा के न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने आरोपी गुलाबचंद को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

विवाहिता से दुष्कर्म- उदयपुर जिले के ओगणा थाना पुलिस ने एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बताया गया कि मामला 25 जनवरी का है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने मकान में सो रही थी। इसी दौरान अंबावा निवासी लालू पुत्र नाना गमेती उसके घर में आया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी लेकिन उन्होंने लोकलाज के भय दिखाते हुए मामला दर्ज कराने से रोका। इसके बाद आरोपी उसके साथ छेड़खानी करने लगा और उसने देरी से मामला दर्ज कराया।

दिल्ली की पत्रकार को धमकी देने वाले को नहीं मिलेगी माफी, पत्रकार का बयान दर्ज कर दिल्ली से लौटी उदयपुर पुलिस

उदयपुर । दिल्ली की महिला पत्रकार को ट्वीटर पर दुष्कर्म तथा हत्या की धमकी देनेवाले आरोपी को माफी नहीं मिलेगी। इस मामले के जांच अधिकारी उदयपुर से दिल्ली पहुंचे तथा उसके बयान दर्ज किए। इस बीच आरोपी को अदालत के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उदयपुर पुलिस ने आरोपी कपिल सिंह वियान के गिरफ्तार किए जाने की जानकारी पत्रकार को ट्वीट कर दी तो उसने पुलिस से अपील की थी कि आरोपी को चेतावनी देते हुए रिहा किए जाने की मांग की थी। इधर, उदयपुर पुलिस ने साफ किया है कि आरोपी को माफी संभव नहीं है। रविवार को मामले की जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामनारायण सिंह को दिल्ली भेजा गया। पत्रकार के बयान दर्ज करने के बाद वह उदयपुर लौट आए। पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार का कहना है कि आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है जिससे उसने ट्वीट किया। उल्लेखनीय है कि उदयपुर के लॉ स्टूडेंट कपिल सिंह वियान ने दिल्ली की पत्रकार के ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए उसे दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बार पत्रकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राजस्थान पुलिस को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी तथा कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद उदयपुर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार ने बताया कि जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने उसके सेमारी स्थित आवास पर पहुंची तो वह आलमारी में छिपकर बैठ गया। उसने अपने परिजनों से बाहर से आलमारी बंद करने को कह दिया था, जबकि पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाशते हुए उस आलमारी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया।

गुजरात भाजपा संसदीय बोर्ड की पहली बैठक: महानगरपालिका प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर

अहमदाबाद । गुजरात भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की सोमवार को पहली बैठक होगी। इसमें महानगरपालिका के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने एक सप्ताह पहले ही प्रदेश की संसदीय बोर्ड का गठन किया था।

पाटिल ने संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा, कृषि मंत्री आरसी फलदू सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं को इसमें शामिल किया लेकिन पूर्व अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को बोर्ड से बाहर रखा। आगामी 21 फरवरी को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर महानगर पालिका के चुनाव होंगे। प्रदेश भाजपा का संसदीय बोर्ड अपनी बैठक में महानगरपालिका के प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देगा।

भाजपा ने एक लंबी कवायद के बाद प्रत्याशियों के चुनाव के लिए एक एक सीट पर अलग-अलग पैनल तैयार किए हैं। पैनल में एक सीट पर 3 नाम रखे गए हैं इनमें महिलाओं को खास प्रमुखता दी गई है। उधर गुजरात कांग्रेस की महानगर पालिका चुनाव से पहले सरकार को घेरने के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार तथा किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर चुकी है।

गुजरात की सभी आठ महानगरपालिका ऊपर हाल भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस कोरोना महामारी तथा केंद्र सरकार के 3 किसान बिलों को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भाजपा की राज्य सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस को इस चुनाव में सफलता की उम्मीद नजर आ रही है हालांकि बीते माह हुए विधानसभा उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर अपने तेवर जता दिए थे। मुख्यमंत्री रुपाणी तथा भाजपा अध्यक्ष पाटिल की जोड़ी की यह सबसे पहली शानदार जीत थी।

महाप्रभु लिंगराज मंदिर के चहुंओर मौजूद प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए धर्मेन्द्र प्रधान ने पर्यटन मंत्री को लिखा पत्र

भुवनेश्वर । भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र खासकर प्रभु लिंगराज एवं शुकशारी मंदिर के चारों तरफ मौजूद शताब्दी के प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा एवं पुनरूद्धार के लिए तुरन्त व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने को केन्द्र संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पत्र लिखकर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अनुरोध किया है। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) विशेषज्ञ टीम को भुवनेश्वर भेजने को निर्देश देने के साथ ही इस क्षेत्र की खुदाई कर विस्तृत रूप से अनुसंधान करने की दिशा में हस्तक्षेप करने को भी प्रधान ने पत्र के जरिए अनुरोध किया है। केन्द्र मंत्री प्रधान ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि हाल ही में एएसआई की भुवनेश्वर शाखा द्वारा मंदिर मालिनी शहर भुवनेश्वर के एकाम्र क्षेत्र में मौजूद शूकशारी मंदिर के पास 2 एकड़ जमीन में खुदाई कार्य हुआ है। खुदाई के समय शारी मंदिर के उत्तर-पश्चिम 1 से 2 मीटर कोण में मौजूद सोमवंशी समय के दशवीं शताब्दी एवं 11वीं शताब्दी के अमूल्य भग्नावशेष मिले हैं। एएसआई हाल ही में दो ढांचे का भी अविष्कार किया है, जो कि शारी मंदिर के भग्नावशेष के तौर पर पता चल रहा है। मिले रहे तथ्य के मुताबिक एएसआई के विशेषज्ञों ने कहा है कि शारी मंदिर पंचायतन ढांचे में बनाया गया है। जिसमें चार छोटे-छोटे मंदिर हैं। इससे एकाम्र क्षेत्र में जमीन के नीचे अनेकों ऐतिहासिक ढांचा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भुवनेश्वर स्थित शुकशारी मंदिर एवं प्रभु लिंगराज मंदिर के प्राचीन कीर्ति एवं प्रत्नतत्व विभाग तथा भग्नावशेष कानून (एमएएसआई) के अधिन में एएसआई द्वारा सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में इस अमूल्य तथा पुराने ओडिशा के प्राचीन कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

ओडिशा के प्राचीन मंदिर के स्थापत्य, कार्य सम्पन्न, सामाजिक संस्कृति एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र खासकर महाप्रभु श्री लिंगराज एवं शुकशारी मंदिर के समीप एक एएसआइ विशेषज्ञ टीम को भेजने के लिए निर्देश देने को प्रधान ने केन्द्र संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से अनुरोध किया है। प्रधान ने कहा है कि इससे जमीन के नीचे मौजूद ऐतिहासिक ढांचे का पुनरूद्धार निर्धारित समय में हो सकेगा।

भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97 फीसदी, सिर्फ 1.56फीसदी आबादी कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली एजेंसी । देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है और कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या में निरंतर इजाफे से रिकवरी दर बढ़कर 97 फीसदी पर आ गई है वहीं सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इस बीच देश में अब तक 37 लाख 68 हजार 843 लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया जा चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 11 हजार 427 नए मामले सामने आए जिससे संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ सात लाख 57 हजार से अधिक हो गया है। इसी दौरान 11 हजार 858 मरीज स्वस्थ हुए जिसके साथ कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या एक करोड़ चार लाख 34 हजार 983 हो गई है। वहीं, सक्रिय मामले 549 घटकर 1 लाख 68 हजार 235 रह गए हैं। इस दौरान देश में 118 मरीजों की कोरोना से मौत हुई और मृतकों का आंकड़ा एक लाख 54 हजार 392 हो गया है।

महाराष्ट्र में कोरोना मामलों का घटना-बढ़ना जारी- देश में रिकवरी दर बढ़कर 97 प्रतिशत और सक्रिय मामलों की दर घटकर 1.56 फीसदी रह गई है जबकि मृत्युदर अभी 1.44 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामले घटने-बढ़ने का क्रम जारी है और पिछले दो दिन से यहां इनमें बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 875 सक्रिय मामले बढ़े और इनकी संख्या अब 46 हजार 312 हो गई है। इससे पहले रविवार को 1 हजार 53 सक्रिय मामले बढ़े थे। राज्य में 1670 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 19.29 लाख हो गई है जबकि 40 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 51 हजार 82 हो गया है।

केरल में क्या है हाल- केरल में इसी दौरान 485 सक्रिय मामले कम हुए हैं और सबसे अधिक 5730 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामले अब 71,229 रह गये हैं, वहीं कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8.54 लाख हो गया है जबकि 21 और मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या 3743 हो गई है। सक्रिय मामलों में केरल अभी भी पहले स्थान पर है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सक्रिय मामले 75 कम हुए हैं और इनकी संख्या अब 1361 रह गयी है। वहीं

चार और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 हजार 853 हो गया है। दिल्ली में अब तक 6 लाख 22 हजार से अधिक मरीज कोरोनामुक्त हुए हैं।

कर्नाटक-तेलंगाना में क्या है स्थिति- देश के दक्षिणी राज्य कनार्टक में कोरोना के सक्रिय मामले 53 बढ़कर 6 हजार 48 हो गए हैं। राज्य में मृतकों का आंकड़ा 12 हजार 217 हो गया है और अब तक 9 लाख 21 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। तेलंगाना में सक्रिय मामले घटकर 2 हजार 92 रह गये हैं और 1601 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लाख 90 हजार से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं।

आंध्र प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा ने जीती कोरोना से जंग- आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 1278 रह गए हैं। वहीं 127 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 8 लाख 79 हजार से अधिक हो गई है जबकि 7 हजार 153 लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4554 रह गयी है तथा अभी तक 12 हजार 356 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 8 लाख 21 हजार से अधिक मरीज संक्रमणमुक्त हुए हैं।

यूपी-पंजाब-बंगाल में क्या हैं हालात- आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामले 157 कम होकर 5525 रह गए हैं। इस महामारी से 8658 लोगों की मौत हो चुकी है तथा अब तक 5 लाख 86 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के सक्रिय मामले कम होकर 5 हजार 553 रह गए हैं और 10 हजार 173 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 5.54 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। पंजाब में सक्रिय मामले 56 घटकर 2128 हो गए हैं। यहां संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या 1.65 लाख से अधिक हो गई है जबकि 5615 मरीजों की जान जा चुकी है।

मध्य प्रदेश में 2 लाख 48 हजार से ज्यादा ठीक हुए- मध्य प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 2 हजार 665 रह गए हैं तथा अब तक 2.48 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 3810 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं, छत्तीसगढ़ में सक्रिय मामले 67 बढ़कर 4327 हो गए हैं। राज्य में 2.97 लाख से अधिक लोग कोरोनामुक्त हो चुके हैं, वहीं तीन और लोगों की इस महामारी के संक्रमण से मौत होने के साथ मृतकों की संख्या 3701 हो गई है।

गुजरात में सक्रिय मामले 3450 रह गए हैं तथा 4387 लोगों की मौत हुई है और 2.53 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं। बिहार में सक्रिय मामले 83 घटकर 893 रह गए हैं। राज्य में कोरोना से 1501 लोगों की मौत हुई है जबकि 2.57 लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक हरियाणा में 3018, राजस्थान में 2766, जम्मू-कश्मीर में 1936, ओडिशा में 1906, उत्तराखंड में 1644, असम में 1082, झारखंड में 1072, हिमाचल प्रदेश में 979, गोवा में 768, पुड्डुचेरी में 648, त्रिपुरा में 391, मणिपुर में 371, चंडीगढ़ में 334, मेघालय में 146, सिक्किम में 134, लद्दाख में 130, नागालैंड में 88, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 62, अरुणाचल प्रदेश में 56, मिजोरम में नौ तथा दादर-नागर हवेली एवं दमन-दीव में दो लोगों की मौत हुई है।

किसान आंदोलन के लिए राजनीतिक समर्थन क्यों लिया, राकेश टिकैत ने बताई वजह

नई दिल्ली एजेंसी । गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद ऐसा लगा जैसे अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, मगर राकेश टिकैत ने इसे बचाए रखा। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में राजनीतिक दलों को नहीं घुसने दिया था लेकिन प्रदर्शन स्थलों पर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद ही उसने राजनीतिक समर्थन लिया।

गाजीपुर में दिल्ली-मेरठ राजमार्ग पर प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसानों के जुटने की पृष्ठभूमि में टिकैत ने यह टिप्पणी की।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर सीमा पर जुट रहे हैं। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन अपनी गति खोने लगा था लेकिन टिकैत के भावुक अपील और मुजफ्फरनगर में आज आयोजित महापंचायत ने आंदोलन में जान फूंक दी है।

एक सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन में प्रवेश नहीं करने दिया था क्योंकि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। प्रदर्शन को लेकर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद, राजनीतिक दलों से समर्थन लिया गया। इसके बावजूद, नेताओं को किसान आंदोलन के मंच से दूर रखा गया है।

गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत से मिलने आए शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, %मोदी साब नु किसाना दी मन दी गल सुननी चाहिदी है। शिअद कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र में सत्तारूढ़ राजग से रिश्ता तोड़ चुका है। बता दें कि बीते दिनों जब पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कराने की तैयारी कर ली थी, तभी राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे माहौल को बदल दिया और पुलिस को पीछे हटना पड़ा था।

राजस्थान में मासूम से हैवानियत मामले में देरी से मामला दर्ज करने पर मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी,आईजी और एसपी को जारी किया नोटिस

उदयपुर । राजसमंद में सात साल की मासूम से बेरहमी के मामले में देरी से मामला दर्ज किए जाने पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी, उदयपुर आईजी तथा राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। जिसमें उनसे पूछा गया है कि थाने में पीड़िता के लाए जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में देरी किस लिए की गई। जबाव के लिए उन्हें पंद्रह दिन का वक्त दिया गया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस महेश चंद्र शर्मा की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है कि सात साल की बालिका से हैवानियत की गई। पुलिस ने ना केवल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने में देरी की, बल्कि उसे थाने से भगाने की भी जानकारी मिली है।

जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत ही जघन्य एवं घृणित घटना है, इससे मानवता शर्मसार हुई है। सात साल की एक बालिका पर किया गया अत्याचार एवं कुंठापूर्ण व्यवहार सभ्य समाज पर एक दाग है। इस प्रकार की घटना समाज में फैल रही विकृति को दर्शाती है एवं घटते सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राजसमंद के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेंद्र कुमार द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ऐसे संवेदनशील मामले में पुलिस द्वारा की गई लापरवाही एवं असंवेदनशीलता राज्य की पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है।

उल्लेखनीय है कि राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के थानेट गांव में सात साल की एक मासूस के साथ अपने ही हैवानियत कर रहे थे। बिना मां की इस बालिका को पिछले कई महीने से उसके रिश्तेदार जो रिश्ते में भाई-भाभी लगते थे, वे उसके शारीरिक और यौन उत्पीडन कर रहे थे। आरोपी ना केवल उसको निर्वस्त कर मारपीट करते, बल्कि लोहे के गर्म सरिए और जलती सिगरेट से दागते थे।

यहां तक उन्होंने मासूम के हाथ-पैर के नाखून तक निकाल लिए। पिछले दिनों उसके साथ हुए अत्याचार का वीडियो वायरल होने पर इसका पता चला और चाइल्ड लाइन संस्था के सदस्य उसके पास पहुंचे तथा ग्रामीणों को साथ लेकर भीम थाने पहुंचे।

जहां आठ घंटे तक पीड़ित बालिका को बिठाए रखा लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बाद में विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गहलोत की दखल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी दंपती किशन सिंह और उनकी पत्नी रेखा को गिरफ्तार कर लिया।

गुजरात में शुरू होगा शिप रिसाइकल का काम, 1624 करोड़ रुपये दिए गए

अहमदाबाद । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा , शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा। 5 साल पुराना आइएनएस विराट युद्धपोत को यहां तोड़ा जा रहा है शिपिंग रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री में अलंग शिपयार्ड का बहुत बड़ा नाम है। कैंबे की खाड़ी में बने इस शिप ब्रेकिंग यार्ड को किसके लहरों के वेग के कारण एक अलग पहचान मिली हुई है। केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री मनसुख मांडवीया के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल लगभग 1000 बड़े जहाज को तोड़ा जाता है। इनमें से करीब 350 से 400 जहाज अकेले अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़े जाते हैं।

1983 में पहली बार तोड़ा गया था जहाज - रक्षा मंत्रालय का 75 साल पुराना आई एन एस विराट को भी तोड़ने के लिए यहीं पर लाया गया है। यहां के एक ट्रेडर हेमराज भाई बताते हैं कि अलंग में 1983 में पहली बार किसी जहाज को तोड़ा गया था। अब तक यहां हजारों जहाज तोड़े जा चुके हैं इसे भावनगर का सबसे बड़ा कारोबार माना जाता है तथा गुजरात तथा गुजरात से बाहर 500000 से अधिक लोग सीधे तौर पर इसके कारोबार से जुड़े हैं। रेवा शंकर भी एक ट्रेडर हैं तथा वे बताते हैं कि जहाज को तोड़ने से पहले प्रदूषण बोर्ड सेफ्टी आदि कई विभागों से मंजूरी लेनी होती है।

कैसे तोड़ा जाता है जहाज

सबसे पहले जहाज से तेल रिमूव किया जाता है तथा अन्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ वह धातु को अलग किया जाता है इसके बाद शिप को तोड़ने की मंजूरी मिलती है। यहां से दक्षिण भारत, उत्तर भारत सहित कई राज्यों में शिप का फर्नीचर लोहा सरिया तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बिकती हैं। राजस्थान में भारी मात्रा में फर्नीचर बेचा जाता है जबकि पंजाब में लोहा बिकता है। जहाज को तोड़ने की शुरुआत केबिन क्रू से होती है।

मुंबईवासियों को बड़ी राहत, आम नागरिकों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू; नए नियम लागू

मुंबई । मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा आम नागरिकों के लिए आज (1 फरवरी) से शुरू कर दी गई है। यात्रियों के लिए रेलवे और राज्य सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं जिससे यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित रहे। रेलवे ने आम नागरिकों की यात्रा के लिए समय में बड़ा बदलाव किया है अब पहली सेवा से सुबह 7 तक, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक और दिन की आखिरी ट्रेन से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खोली जाएंगी। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के कहर के चलते बीते 10 माह से आम नागरिकों को लोकल ट्रेन सेवा से वंचित किया हुआ था।

टिकट के लिए बदले नियम

लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सीजन टिकट दिए जाएंगे, अगर 22 मार्च 2020 से पूर्व लिए गए सीजन टिकट में यदि दिन बचे हैं तो उन्हें नए सीजन टिकट में जोड़ा जाएगा। टिकट बुकिंग क्लर्कों को ग्रेस पीरियड रखने का आदेश दिया गया है। अगर लाइन में भीड़ के कारण आप 7 बजकर 15 मिनट पर काउंटर पर पहुंचते हैं तो टिकट दिया जाएगा, लेकिन भीड़ होनी चाहिये।

बता दें की सामान्य परिस्थितियों में टिकट मिलने के एक घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होती है। इस नियम को रिफंड के लिए लागू किया गया था। एक घंटे बाद अगर यात्रा कैंसिल करनी पड़े तो रिफंड नहीं मिलता लेकिन अब इसे लेकर शर्त लागू की गई है।

इन यात्रियों पर हो सकती है कार्रवाई

लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए रेलवे और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई आम नागरिक बिना अनुमति वाले समय में यात्रा करता हुआ पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महिला यात्रियों के लिए बदले नियम

महिला यात्रियों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे के बाद अनुमति दी गई थी। लेकिन सोमवार 1 फरवरी से महिलाओं को सुबह पहली गाड़ी चलने से लेकर सुबह 7 बजे तक, उसके बाद सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 7 बजे से अंतिम लोकल ट्रेनें तक यात्रा करने की अनुमति दी गई है ।

गुजरात में खुली 9वीं तथा 11वीं कक्षाएं, ट्यूशन क्लासेस को भी खोलने की मंजूरी

अहमदाबाद । गुजरात में सोमवार से कक्षा 9 तथा 11वीं की कक्षाएं भी खुल गई हैं। सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के ट्यूशन क्लासेस को भी खोलने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासामा के अनुसार सोमवार 1 फरवरी से राज्य में कक्षा 9 तथा कक्षा ग्यारहवीं के छात्र छात्राओं को भी स्कूल आने की मंजूरी मिल गई है। छात्र एवं छात्राएं अपने अभिभावकों की सहमति से स्कूल में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शुरू हुई क्लासों में शामिल हो सकते हैं।

कक्षा 10 तथा कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए पिछले माह में ही स्कूल खोल दिए गए थे। सरकार ने बोर्ड परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए भी यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले माह ही स्कूलों को खोलने की रूपरेखा पर चर्चा हुई थी। सरकार ने कक्षा 9 10,11 तथा 12वीं के बच्चों के ट्यूशन क्लासेस को भी खोलने की अनुमति दे दी है।

कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल तथा ट्यूशन क्लासेस को 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खोला गया है। छात्र-छात्राओं को स्कूल में ट्यूशन क्लास में ऑड इवन नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा। राज्य की स्कूल संचालक तथा कुछ अभिभावक संगठन सरकार से लगातार स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे थे।

राज्य में कोरोना संक्रमण का असर भी अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। रविवार को गुजरात में कोरोना संक्रमण का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार को कोरोना संक्रमण के 316 केस रजिस्टर्ड किए गए लेकिन कोरोना के कारण मौत का एक भी आंकड़ा सामने नहीं आया।

बंगाल के लोगों को आर्सेनिक युक्त पानी से मिलेगी मुक्तिः गजेंद्र सिंह शेखावत

कोलकाता । बंगाल की जनता को जल्द आर्सेनिक युक्त पानी से मुक्ति मिलेगी। कोलकाता में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर क्वालिटी बनकर तैयार हो चुका है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को सेंटर का दौरा करने के बाद इसकी जानकारी दी। शेखावत ने कहा कि बंगालवासी दशकों से आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बंगाल की किसी भी सरकार ने जनहित और स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की। मोदी सरकार के नेतृत्व में कोलकाता में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर क्वालिटी बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही यह सेंटर राष्ट्र की सेवा में सुचारू होगा।

प्रत्येक देशवासी मोदीजी के साथ

शेखावत रविवार को अशोकनगर और हाबरा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच रहे। उन्होंने अशोकनगर में गणमान्य लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, वहीं ब्लड डोनेशन, कंबल वितरण समेत कई कार्यक्रमों में भाग लिया।शेखावत ने कहा कि प्रत्येक देशवासी मोदीजी के साथ खड़ा है। यह विश्वास हर दिन आमजन के व्यवहार से मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने अशोकनगर और हाबरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शिरकत की। शेखावत ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्द्धन किया और कहा कि पार्टी की नीतियों को जन-जन पहुंचाएं। तृणमूल के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। शेखावत ने भाजपा की स्थानीय इकाई द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में शेखावत ने गृह संपर्क अभियान में भाग लिया। शेखावत ने केंद्र सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी और कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर जनता को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

किराना का सामान खरीदने पर ट्रोल हुई दीपिका पादुकोण

लोग पूछने लगे- टमाटर का क्या भाव है

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण शुक्रवार को किराना का सामान लेती नजर आई थीं। यूं तो एक सिलेब्रिटी का आम आदमी की तरह जरूरी कामों को करना अच्छी बात है, लेकिन इसे लेकर कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने जेएनयू के मसले से इसे जोड़ते हुए कहा है कि यह उनका पीआर स्टंट है। यूजर ने ट्विटर पर लिखा है, दीपिका पादुकोण खाना भी खाती है तो पीआर के साथ खाती है। हद है। एक अन्य यूजर ने लिखा है, फ्लॉप फिल्म करो, जेएनयू जाओ। फिर यही दिन आएंगे, जब सामान खरीदने का भी मीडिया कवरेज कराना पड़ेगा आपको दीपिका पादुकोण।

वहीं एक यूजर ने दीपिका पादुकोण को ट्रोल करते हुए पूछा है कि टमाटर का क्या भाव है? एक तरफ कुछ यूजर उन्हें ट्रोल करते दिखे तो कुछ लोग यह कहते दिखे कि शायद दीपिका पादुकोण पति के लिए कोई विशेष डिश तैयार करने वाली हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण शुक्रवार को एक शॉपिंग मॉल के बाहर ग्रॉसरी की खरीद के बाद नजर आई थीं। इस दौरान उनके हाथ में कुछ कैरी बैग भी थे। इसके बाद वह पति रणवीर सिंह के साथ डिनर करती हुई एक रेस्तरां में दिखी थीं। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत सोशल मीडिया से अपनी सभी पुरानी पोस्ट्स को हटा दिया था। इसके बाद से वह अब एक ऑडियो डायरी के नाम से कार्यक्रम कर रही हैं।

पेशवर तौर पर बात करें तो दीपिका पादुकोण फिलहाल पठान मूवी की शूटिंग में बिजी हैं। इस ऐक्शन मूवी में उनके साथ एक्टर शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वह एक और फिल्म कर रही हैं, जिसमें वह अमिताभ बच्चन और बाहुबली फेम एक्टर प्रभास के साथ नजर आने वाली हैं।

एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने घरेलू कामों को लेकर कहा था कि मेरी जिंदगी भी किसी आम इंसान सरीखी है और वह अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती हैं। दीपिका पादुकोण ने कहा था कि उनके पति रणवीर सिंह अकसर कहते हैं कि वह ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन मुझे खुद से काम करना पसंद है।

पंजाबी सिंगर काका और अभिनेत्री कनिका मान

ने की शादी? जानिए VIRAL तस्वीरों की सच्चाई

छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री कनिका मान (Kanika Mann) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें साझा करती रहती हैं। लेकिन हाल ही में कनिका की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे बाद फैन्स ऐसा कह रहे हैं कि अभिनेत्री ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। एक ओर जहां फैन्स अभिनेत्री के लिए प्यार जाहिर कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर हैरानी भी जता रहे हैं।दरअसल पंजाबी सिंगर काका (Punjabi singer Kaka) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में काका के साथ कनिका मान नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में जहां काका, कनिका को घुटने पर बैठकर प्रपोज कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक दूसरे को हग करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर में दोनों कैमरे को देख पोज दे रहे हैं। काका द्वारा शेयर की गई फोटोज में व्हाइट आउटफिट के साथ सिर पर फ्लॉवर का बना क्राउन पहनीं कनिका बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं, ब्लैक सूट में काका भी काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं। बता दें कि फोटोज को शेयर करते हुए काका ने एक दिल के इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, वह प्यार है। वहीं काका के इस पोस्ट पर कनिका ने भी कमेंट किया है। कनिका ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, वह। इसके साथ उन्होंने भी दिल का इमोजी शेयर किया है। याद दिला दें कि काका के अलावा कनिका ने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें वो कुर्सी पर बैठकर खाना खाती नजर आ रही हैं। कनिका ने फोटो कैप्शन में लिखा है, इसलिए वो मुझसे कहते हैं कि तुम मेरी जैसी लड़की की तलाश करो।इन सभी तस्वीरों के वायरल होने के बाद फैन्स ऐसा कयास लगा रहे हैं कि कनिका और काका ने शादी कर ली है, हालांकि दोनों का अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शादी की कयास के दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि ये उनके अपकमिंग वीडियो सॉन्ग की तस्वीरे हैं। इस बात का अंदाजा कनिका के द्वारा शेयर किए गए उस पुराने वीडियो से लगाया जा रहा है, जो उन्होंने 19 जनवरी 2021 को शेयर किया था। इसके कैप्शन में कनिका ने लिखा था, वे मेरे तेरे पीछे। गौरतलब है कि कनिका ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों और एलबम्स में भी काम किया। छोटे पर्दे पर शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' से उन्हें सफलता मिली। वहीं फिलहाल कनिका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के दूसरे सीजन में काम कर रही हैं। बता दें कि कनिका का नाम अभिनेता निशांत मल्कानी से भी जोड़ा जाता है।

सास के साथ शिल्पा शेट्टी ने साझ किया वीडियो, इस खास कैप्शन से जीता फैन्स का दिल

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा शिल्पा शेट्टी अपने अनोखे स्वैग क चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया प सक्रिय रहती हैं और अक्सर फैन्स के साथ अपनी तस्वीरें औ वीडियोज साझा करती रहती हैं। वहीं फैन्स भी शिल्पा की तस्वी और वीडियोज को भरपूर प्यार देते हैं। ऐसे में एक बार फिर शिल शेट्टी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते चर्चा में हैं।

दरअसल कुछ देर पहले ही शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर ए वीडियो पोस्ट किया है। तस्वीरों से बने हुए इस वीडियो अभिनेत्री के साथ उनकी सास नजर आ रही हैं। वीडियो में शिल और उनकी सास, साथ में क्वालिटी टाइम बिताते और हंस मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शिल्पा हमेशा की तर बेहद खूबसूरत लग रही हैं।वीडियो के साथ ही शिल्पा के सोश मीडिया पोस्ट का कैप्शन भी चर्चा में है। शिल्पा ने लिखा है कि व अपनी ड्रीमी सासू मां से उनके बेटे राज कुंद्रा के बारे में गपशप क रही हैं। वीडियो के साथ इस कैप्शन को भी फैन्स काफी पसंद क रहे हैं। करीब एक घंटे में ही शिल्पा के इस पोस्ट पर ढाई ला लाइक्स आ चुके हैं। वहीं फैन्स कमेंट सेक्शन में भी सास- बहू क तारीफ कर रहे हैं।वैसे बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है ज शिल्पा ने अपनी सासू मां के लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट साझ किया हो। इससे पहले भी शिल्पा उनके साथ और उनके बारे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुकी हैं। अप्रैल 2020 में भी शिल ने अपनी सास की तारीफ करते हुए एक वीडियो साझा किया थ जिसमें वो एक्सरसाइज करते नजर आ रही थीं। वीडियो में खुद शिल्पा दिखती हैं और कहती हैं- स्वस्थ रहो और मस्त रहो।शिल ने वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था, %%मेरी 6 साल की सास वर्कआउट करती हुई। ये काफी इंस्पायरिंग है। व डायबिटिक हैं, लेकिन वह एक्सरसाइज, टहलने और योगा कर के लिए भी समय निकाल ही लेती हैं। वह अपनी लाइफ अनुशासन रखती हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। उनक ये वीडियो हर किसी को सिखाता है कि किसी भी उम्र में शुरुआत की जा सकती है।इसके अलावा शिल्पा ने अपनी सास जन्मदिन पर भी एक प्यारा वीडियो साझा किया था और अप प्यार उनके लिए जाहिर किया था। बात शिल्पा के प्रोफेशन करियर की करें तो अभिनेत्री जल्दी ही हंगामा 2 और निकम्मा नजर आएंगी।

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने ट्रोल को दिया मुंहतोड़ जवाब, जानें- क्या है पूरा मामला

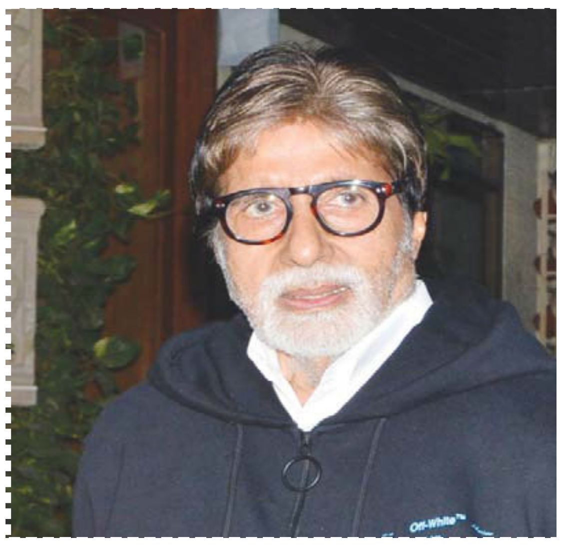

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली अकसर सोशल मीडिया सक्रिय रहती हैं और अपने बारे में अकसर तमाम जानकारि फॉलोअर्स से साझा करती रहती हैं। नव्या ने हाल ही में 'नवेली' नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसे लेकर उन्हें सोश मीडिया पर काफी सराहना मिल रही है। वहीं कई बार उन्हें ट्रोल्स भी सामना करना पड़ा है। ऐसे ही एक ट्रोल को नव्या नवेली ने कर जवाब दिया है। दरअसल नवेली प्रोजेक्ट के ऑफिशियल पेज नव्या ने लिखा था, नवेली प्रोजेक्ट के जरिए हम भारत में जेंडर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए हम महिलाओं संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रय करेंगे। यह आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए होगा।

उनकी इस पोस्ट पर तमाम यूजर्स ने नव्या नवेली की सराहना की लेकिन कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया। ऐसे ही एक यूजर्स लिखा है, पहले तुम्हें ही नौकरी की जरूरत है। फिर तुम यह सब क् कर सकती हो। इस पर नव्या ने यूजर को करारा जवाब देते हुए लि है,मेरे पास वास्तव में काम है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कॉमेंट हार्ट इमोजी भी पोस्ट किया है। नव्या नवेली आरा हेल्थ की स संस्थापक भी हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो महिलाओं स्वास्थ्य से जुड़े मसले पर काम करता है। पिछले दिनों इंस्टाग्र लाइव के दौरान नव्या नवेली ने बताया था कि कैसे महिलाओं इंडस्ट्री में कम आंका जाता है और लड़की होने के चलते उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है।नव्या नवेली ने कहा था, ज आप लोगों से मिलने जाते हैं तो फिर आपको खुद को प्रूव कर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि पूरी इंडस्ट्री ही पुरुष प्रधान है। य नहीं नव्या नवेली ने कहा था कि वह जब अपने काम के सिलसिले किसी वेंडर या फिर डॉक्टर से बात करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह गंभीरता से नहीं ले रहा है और बात करके एक तरह से द कर रहा है। नव्या नवेली अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अ कारोबारी निखिल नंदा की बेटी हैं। निखिल नंदा एस्कॉर्ट्स ग्रुप सीईओ हैं। पिछले दिनों ही उन्हें भारत के बेस्ट सीईओ के खिताब नवाजा गया था।

महिला हॉकी टीम लगातार दूसरा ओलंपिक खेलेगी

बेंगलुरु, (एजेंसी)। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेगी। भारतीय टीम की अनुभवी गोलकीपर रजनी एतिमार्पू के अनुसार अगर आगामी टोक्यो ओलंपिक में अगर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो खेल की ओर महिलाओं का रुझान बढ़ेगा। रानी के नेतृत्व वाली टीम ने साल 2019 में एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर जीतकर लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों के लिए प्रवेश हासिल किया है। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहीं रजनी ने कहा, टोक्यो ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने से निश्चित रूप से खेल की ओर रुचि बढ़ेगी और यह निश्चित रूप से अधिक महिलाओं को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करना सही मानते हैं पूर्व क्रिकेटर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटरों ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रणजी ट्राफी का आयोजन नहीं करने का जो फैसला किया है वह पूरी तरह ठीक है। यह पहली बार है जब रणजी ट्रॉफी नहीं हो रही है। रणजी के आधार पर ही भारती टीम में चयन की परंपरा रही है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर चंद्रकांत पंडित ने कहा कि खिलाड़ियों को इसके नहीं होने से नुकसान तो है पर अभी के हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने जो भी फैसला किया है वह सभी के सेहत की सुरक्षा को देखते हुए जरुरी है। बीसीसीआई ने अपनी मान्यता प्राप्त इकाइयों को जानकारी दी है कि संशोधित सत्र में विजय हजारे ट्रॉफी, सीनियर महिला एकदिवसीय टूनार्मेंट और अंडर-19 वर्ग में लड़कों के लिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कम से कम दो टूनार्मेंटों का आयोजन हो रहा है। अंडर-19 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई को कम समय में वीनू मांकड़ ट्रॉफी का आयोजन भी करना था। पूर्वोत्तर के राज्यों के शामिल होने के बाद घरेलू टूनार्मेंट में 38 प्रथम श्रेणी टीमें हो गई हैं और कोच वसीम जाफर ने व्यावहारिक मुश्किलों का हवाला दिया। उसी के बाद रणजी को आयोजित नहीं करने का फैसला हुआ। जाफर ने कहा कि आदर्श स्थिति में मैं चाहता कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन हो पर तकरीन 38 टीमों के साथ, इतने सारे खिलाड़ी, स्थल और बाकी चीजों को देखते हुए संभवतः साजो सामान के लिहाज से यह थोड़ा मुश्किल होता। बीसीसीआई ने हालांकि घरेलू खिलाड़ियों को मुआवजे का वादा किया है और इससे उन्हें कुछ वित्तीय राहत मिल सकती है। घरेलू क्रिकेट के एक अन्य दिग्गज खिलाड़ी अशोक मल्होत्रा का मानना है कि रणजी ट्रॉफी के आयोजन के लिए चार महीने तक जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहना कभी भी व्यावहारिक विचार नहीं था। बंगाल के गेंदबाजी कोच राणादेब बोस ने भी कहा कि जैविक रुप से सुरक्षित माहौल में हर दूसरे दिन आपका परीक्षण होता है। बोस ने कहा कि रणजी ट्रॉफी लगभग चार महीने का टूनार्मेंट है। इतने समय तक अपने परिवार से दूर अल-थलग रहना मानसिक सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है।

मेलबोर्न में जापान की मिसाकी डोई ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में शॉट खेलती हुई।

काहिरा में पुरुष विश्व कप हैंडबाल में जीत के बाद उत्साहित डेनमार्क की टीम।

भारत-इंग्लैंड दूसरे टेस्ट को देख सकेंगे 50 फीसदी दर्शक

चेन्नई, (एजेंसी)। भारत और इंग्लैंड के बीच यहां होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच को 50 फीसदी दर्शक देख सकेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए यहां के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में 50 फीसदी दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। टीएनसीए के एक शीर्ष अधिकारी ने साथ ही कहा है कि इसके साथ ही मीडिया को भी स्टेडियम में प्रेस बॉक्स से दोनों टेस्ट मैचों को कवर करने की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 से नयी दिशा-निर्देश के जारी होने के बाद इस मामले पर टीएनसीए के सदस्यों के बीच बात हुई। टीएनसीए और बीसीसीआई अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इसकी अनुमति दी गई है। नये दिशा-निर्देश में खेल स्थलों में दर्शकों के प्रवेश की मंजूरी का प्रावधान है। टीएनसीए अधिकारी ने कहा कि खेल स्थलों को लेकर कोविड-19 से जुड़ी केन्द्र सरकार के नये दिशानिर्देश में दर्शकों की मंजूरी मिलने और राज्य सरकार से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के जारी होने के बाद हमने भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए दर्शकों को अनुमति देने पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि बीसीसीआई और टीएनसीए द्वारा सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूसरे टेस्ट के लिए 50 फीसदी दर्शकों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। चिदंबरम स्टेडियम की क्षमता 50,000 है। श्रृंखला का पहला टेस्ट शुक्रवार से शुरू हो रहा है जबकि दूसरा मैच 13 फरवरी से होगा। अहमदाबाद में तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए पहले ही दर्शकों को मंजूरी मिल गई है। अधिकारी ने यह भी कहा कि मीडिया को स्टेडियम में प्रेस बॉक्स से दोनों टेस्ट मैचों को कवर करने की अनुमति दी जाएगी हालांकि संवाददाता सम्मेलन हालांकि अब भी ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

भारतीय महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना दौरा ड्रॉ के साथ समाप्त

ब्यूनस आयर्स, (एजेंसी)। भारतीय महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना दौरा ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ है। दोनो ही टीमों के बीच चौथा और अंतिम मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। भारतीय टीम की कप्तान रानी ने 35वें मिनट में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल किया। वहीं मेजबानों की ओर से एमिलिया फोरचेरियो ने पेनल्टी स्ट्रोक पर एक गोल दागा। यह भारतीय टीम का चौथा मैच था जबकि तीसरा मैच बारिश की बाधा के कारण नहीं हुआ था। इससे पहले भारतीय टीम का मुकाबला अर्जेंटीना की जूनियर टीम से 2-2 और 1-1 से ड्रॉ रहा जबकि अर्जेंटीना की बी टीम के हाथों उसे 1-2, 2-3 से हार का सामना करना पड़ा है। अर्जेंटीना की सीनियर टीम के खिलाफ भारतीय टीम पहले ही दो मैच 2-3, 0-2 से हार गई थी। वहीं आखिरी मैच में भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरी थी पर अनुभवी मेजबान टीम के सामने वह टिक नहीं पायी।

मेजबान टीम ने पहले क्वार्टर से ही हमले बोलने शुरू कर दिए जिससे भारतीय डिफेंस पर दबाव बन गया। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर के तीन मिनट के अंदर ही दो पेनल्टी कॉर्नर बनाए पर भारतीय गोलकीपर सविता ने इन्हें विफल कर दिया। भारतीय टीम को भी 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला पर टीम उसका लाभ नहीं उठा पायी। वहीं दूसरे क्वार्टर में तीन मिनट बाद रानी को एक और अवसर मिला जब अनुभवी वंदना कटारिया ने उनकी मदद की पर भारतीय टीम की कप्तान अर्जेंटीना के डिफेंस को तोड़ नहीं पायी। अर्जेंटीना ने 23वें और 24वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किये पर वह गोल नहीं कर पायी। तीसरे क्वार्टर में एक बार फिर वंदना की सहायता से रानी ने गोल किया। भारत को 39वें और 50वें मिनट में अवसर मिले पर टीम गोल नहीं कर पायी जबकि मेजबान टीम ने 55वें मिनट में मिले पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल कर स्कोर बराबर कर दिया। यह गोल फोरचेरियो ने किया।

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं चंद्रशेखर और वेंकटराघन

चेन्नई, (एजेंसी)। भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच यहां पांच फरवरी से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम को अपने घरेलू मैदान का लाभ मिलेगा। भारतीय टीम के युवा गेंदबाजों ने हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन किया था जिससे टीम के हौंसले बुलंद हैं। वहीं दूसरे और मेहमान टीम इंग्लैंड भी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में मिली 2-0 की जीत से उत्साहित है और उसका लक्ष्य भी इस सीरीज को जीतना रहेगा। भारतीय टीम की कप्तानी जहां विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली के पास है जबकि इंग्लैंड की कमान जो रुट के पास है। रुट भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की दौड़ में शामिल हैं। इस सीरीज में दोनों ही टीमों के गेंदबाजों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। चेन्नई की पिच को देखते हुए कहा जा रहा है कि पहले दिन से ही धीमे गेंदबाजों का दबदबा रहेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा सफल रहे गेंदबाजों के नाम हैं।

भागवत चंद्रशेखर और एस वेंकटराघनः स्पिन की चौकड़ी के मशहूर भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज भागवत चंद्रशेखर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। इस दिग्गज स्पिनर ने कुल 95 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज भारत ने 1971 में जीती, जिसमें चंद्रशेखर ने 13 विकेट लिए थे। चंद्रशेखर के साथ एस वेंकटराघन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ 95 ही विकेट लिए थे। वह इंग्लैंड के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज थे।

अनिल कुंबलेः अनिल कुंबले 19 मैचों में 92 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 90 के दशक में कुंबले ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और 3 विकेट लिए। कुंबले ने एक बार 10 और 4 बार पांच विकेट लिए।

बिशन सिंह बेदीः पूर्व भारतीय कप्तान बेदी ने 27 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 85 विकेट लिए थे। 1971 की सीरीज जीत में बेदी ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 11 विकेट लिए थे। उन्होंने अंतिम टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ 1979 में खेला था।

कपिल देवः इंग्लैंड में सीरीज जीतने वाले तीन कप्तानों में से एक महान ऑलराउंडर कपिल देव ने इंग्लैंड के खिलाफ 85 विकेट लिए थे। उन्होंने 4 बार 5-5 विकेट लिए। कपिल के नेतृत्व में 1986 में भारत ने दूसरी टेस्ट सीरीज जीती थी। उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 से हराया। 85 विकेट लेने के साथ कपिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 शतक और 8 अर्द्धशतकों के साथ 1355 रन भी बनाए हैं।

इशांत शर्मा और आर अश्विनः इशांत शर्मा और आर अश्विन का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। इशांत ने साल 2014 में 17 टेस्ट मैचों में 56 विकेट लिए। उन्होंने दो बार 5-5 विकेट लिए। वहीं अश्विन ने 15 टेस्ट में 56 विकेट लिए थे।

नटराजन ने मुरुगन मंदिर में अपने बाल अर्पित किये

चेन्नई, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज टी नटराजन ने भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपना सिर मुंडवा लिया है। नटराजन ने तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर में अपने बाल अर्पित किये। नटराजन यहां के चिन्नपामपट्टी गांव के रहने वाले हैं और धार्मिक मान्यता के तहत उन्होंने अपने बाल अर्पित किये हैं। आईपीएल 2020 में शानदार प्रदर्शन के कारण नटराजन को टीम इंडिया की टी20 टीम में जगह मिली थी पर कई खिलाड़ियों के फिट न होने से उन्हें एकदिवसीय और टेस्ट में भी जगह मिली गयी। एक ही दौरे पर तीनों प्रारुपों में जगह मिलने के लिए नटराजन ने भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। नटराजन ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट की जिसपर उन्होंने लिखा, अच्छा महसूस कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी नटराजन ने अपने डेब्यू वनडे में 2 विकेट लिये। इसके बाद उन्होंने तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए थे। नटराजन का वतन वापसी के बाद भव्य स्वागत हुआ था। नटराजन जब सलेम में अपने घर पहुंचे तो लोगों ने उनपर फूलों की बरसात की थी।

आईपीएल से कमाई में शीर्ष पर हैं धोनी, रोहित दूसरे और विराट तीसरे नंबर पर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे अधिक कमाई करने वाले क्रिकेटर बन गये हैं। धोनी आईपीएल से 150 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। धोनी की आईपीएल 2020 के रिटेंशन डे से पहले कमाई 137 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही धोनी का अनुबंध बढ़ा उनका नाम रिकार्ड बुक में आ गया है। धोनी साल 2008 से ही सीएसके के कप्तान रहे हैं। ऐसे में उनका वेतन अब 15 करोड़ रुपये है। उन्हें 2018 से इतनी रकम मिल रही है। धोनी आईपीएल 2008 की नीलामी में सबसे बड़े खिलाड़ी थे और तब वह सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर बिके थे। उन्हें सीएसके ने 6 करोड़ करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके बाद अगले तीन साल तक उनकी कमाई इतनी ही रही थी। साल 2011 में बीसीसीआई ने रिटेंशन की कीमत को बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया। इसके बाद 2011 से 2013 के बीच आईपीएल में धोनी का वेतन 8.28 करोड़ रुपये रहा। आईपीएल में साल 2014 की मेगा नीलामी से पहले बीसीसीआई ने एक बार फिर से उन्हें बरकरार रखने की रकम को बढ़ाया है। ऐसे में साल 2014 और 2015 में आईपीएल से धोनी की कमाई 12.5 करोड़ हुई। इसके बाद 2016 और 2017 में धोनी सीएसके पर प्रतिबंध के बाद राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के साथ थे। इस दौरान उनका वेतन 25 करोड़ रुपये था। तीन बार के आईपीएल खिताब विजेता कप्तान धोनी ने साल 2018 में लीग में वापसी के बाद से सीएसके में 60 करोड़ रुपये कमाए हैं। 150 करोड़ रुपये से अधिक के संयुक्त वेतन वाले वह एकमात्र खिलाड़ी हैं। वहीं आईपीएल कमाई में दूसरे नंबर पर मुम्बई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित ने लगातार चौथे सत्र के लिए आरसीबी के कप्तान विराट कोहली की तुलना में 2 करोड़ रुपये कम कमाए हैं पार इसके बाद भी वह कुल कमाई में विराट से आगे हैं।

रोहित अब आईपीएल की शुरूआत से ही सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में से एक हो गये हैं, उन्होंने तक 146.6 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। उन्होंन साल 2018 से मुंबई इंडियंस से 15 करोड़ रुपये अधिक कमाऐ हैं।

ओरलैंडो में अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में खेलते हुए ट्रिनिडाड व टोबेगो के डिफेंडर लीलैंड आर्चर व गोलकीपर एड्रियन फोनसेटे।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव बुधवार को, पर्यवेक्षक भेजेगा एआईबीए : क्रेमलेव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने कहा है कि बुधवार को होने वाले भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। बीएफआई ने इससे पहले कहा था कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए विश्व संस्था अपने पर्यवेक्षक भेजे। क्रेमलेव ने साथ ही कहा कि बीएफआई के साथ लंबित भुगतान को लेकर विवाद सुलझने के बाद भारत के साथ एआईबीए के रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। क्रेमलेव ने कहा, हमारे भारत सहित सभी राष्ट्रीय महासंघों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। विश्व चैंपियनशिप के सभी तरह के भुगतान को लेकर मुद्दा सुलझ गया था और इस मामले को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हम निश्चित तौर पर एआईबीए से एक सक्षम पर्यवेक्षक को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए भेजेंगे। हमरा काम यह तय करना है कि प्रत्येक महासंघ में पूर्ण पारदर्शिता और लोकतंत्र हो। बीएफआई के सूत्रों के अनुसार चुनाव पर्यवेक्षक के मंगलवा या फिर चुनाव के दिन पहुंचने की उम्मीद है पर कोविड-19 परीक्षण के नेगेटिव परिणाम आने पर ही उन्हें चुनाव के दौरान वहां रहने की इजाजत मिलेगी।

बीएफआई अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह को मुंबई क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार से चुनौती मिल रही है। क्रेमलेव ने कहा, मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं, मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों और कोचों का भला हो। अपने राष्ट्रीय महासंघों के साथ एकजुट होकर ही हम आईओसी का भरोसा दोबारा जीत सकते हैं।

क्रेमलेव को उम्मीद है कि इस काम में भारत अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुक्केबाजी मानचित्र में भारत काफी अहम देश है जिसकी समृद्ध विरासत और मजबूत मुक्केबाज हैं। मुझे अपने आधिकारिक दौरे निजी तौर पर भारत आने में खुशी होगी जिससे कि अधिकारियों और खिलाड़ियों से बात कर सकूं। क्रेमलेव ने कहा, मुझे भरोसा है कि भारत एआईबीए की प्रतिष्ठा को बहाल करने के हमारे संयुक्त कार्य में बड़ी भूमिका निभाएगा।

तमिलनाडु ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती

अहमदाबाद, (एजेंसी)। स्पिनर एम सिद्धार्थ के शानदार प्रदर्शन से तमिलनाडु ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी20 टूनार्मेंट जीता है। तमिलनाडु ने खिताबी मुकाबले में बड़ौदा को सात विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में जीत के लिए मिले 121 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु ने सलामी बल्लेबाज सी हरि निशांत 35, बाबा अपराजित नाबाद 29 और कप्तान दिनेश कार्तिक 22 रनों की शानदार पारियों की सहायता से 12 गेंद शेष रहते ही तीन विकेट पर 123 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। शाहरूख खान ने अंत में सात गेंद में नाबाद 18 रन बनाए। इससे पहले सिद्धार्थ ने 20 रन पर चार विकेट लेकर बड़ौदा की टीम को करार झटका दिया। विष्णु सोलंकी 49 और अतित सेठ 29 के बीच सातवें विकेट की 58 रन की साझेदारी के बाद भी बड़ौदा की टीम नौ विकेट पर 120 रन ही बना पायी।

इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की ओर से एन जगदीशन ने 14 और निशांत ने पहले विकेट के लिए 26 रन बनाये। लुकमान मेरिवाला ने जगदीशन को आउट करके टीम को पहला झटका दिया। निशांत और बाबा अपराजित ने इसके बाद स्कोर 67 रन तक पहुंचाया। बाबा शफी पठान ने निशांत को अपना शिकार बनाया। अपराजित और कार्तिक ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया।

इससे पहले तमिलनाडु के कप्तान कार्तिक ने टॉस जीतकर बड़ौदा को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। उसके गेंदबाजों ने शुरूआती विकेट लेकर विरोधी टीम पर दबाव बना दिया और ये सिलसिला अंत तक चला।